अध्यक्ष महोदय : प्रेस का भी कोई फंक्शन है या नहीं ? प्रेस किस लिए हैं। अगर ऐसी खबरें न निकालें तो किस लिए वह हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (Shri K. R. GANESH): The position is that the Pay Commission will submit their Report to the Finance Minister on 31st March. We are not aware of any report which has been submitted. We ourselves do not know how it is coming in the Press. It is for the Pay Commission to decide.

RE. STRIKE IN J.K. MILLS, KANPUR

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Mr. Speaker, Sir, there is a sixty-two day old strike going on in J. K. jute mill at Kanpur. Singhanias are one of the biggest employers in the country and they are owning this mill. I am told that they are not inclined to have any negotiated settlement despite the fact there was a letter by the Union Labour Minister written to the State Labour Minister. One of their demands is regarding piece-work rates and their second demand is about payment of same wages as jute workers in Calcutta are getting. Both the demands are linked up with the policy of the Central Government. I want the Labour Minister to make a statement immediately; otherwise we shall demand that this mill be taken over from J. K. If this matter is not settled within two or three days there is going to be strike in all textile units in Kanpur. If the Labour Minister of U.P. is afraid of J. K. If the Chief Minister of U.P. is afraid of J. K. because of the election funds, I would request the hon. Labour Minister and the hon. Prime Minister that they should come to the rescue of the 4,000 striking workers of this mill. Since the Labour Minister is here, let him make some statement. Mr. Speaker, Sir, I beg of you to ask the Labour Minister to make a statement.

MR. SPEAKER: Mr. Banerjee, there is no question of begging. If he is ready to make a statement, I have no objection. It will be sent to him.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please sit down. What is this going on everyday? I am not going to allow it. I am not going to allow anybody. There is a limit to everything. You go on wasting the time of the House. Nothing from a member who is not permitted by the Chair is going on record.

12.38 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74—*contd.*

MINISTRY OF HOME AFFAIRS—*contd.*

MR. SPEAKER: Further discussion and voting on the Demands for Grants under the central of the Ministry of Home Affairs.

Shri Vajpayee

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : गृह मन्त्रालय की मांगों पर विचार करने से पहले मैं सीमा सुरक्षा दल के उन जवानों तथा अफसरों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित रकना चाहता हूं जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में और बंगला देश के मुक्ति के संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। इस संकट काल में सीमा सुरक्षा दल ने प्रशंसनीय कार्य करके दिखाया है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी पीट ठोंकें और जवानों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके आवास की व्यवस्था की ओर समुचित ध्यान दें। मुझे ग्वालियर के निकट टेकनपुर में उनके प्रशिक्षण केन्द्र में जाने का मौका मिला था। उनकी प्रशिक्षा का प्रबन्ध बहुत उतम है, लेकिन उनके बच्चों के पठन पाठन और आवास के प्रबन्ध में कमी है जिसकी ओर गृह मन्त्रालय का ध्यान जाना चाहिए।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

गृह मंत्रालय को हमारा घरेलू मोर्चा सम्हालना है। गृह मंत्रालय सम्बन्धी रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा गया है कि मोटे तौर पर देश की आन्तरिक सुरक्षा, विधि शासन को बनाये रखना और उन्नत करना, सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने में राज्यों की सहायता करना, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करना तथा केंद्र और राज्यों के सम्बन्ध गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। स्पष्ट है कि देश की एकता की रक्षा गृह मंत्रालय का एक प्रमुख कर्त्तव्य है।

आज देश में एक विस्फोटक वातावरण है। असम में भाषा के सवाल पर व्यापक उपद्रव हुये और सरकार जन धन और सम्मान की रक्षा करने के अपने प्राथमिक कर्तव्य का भी पालन नहीं कर सकी। आंध्र में जो व्यापक जन आन्दोलन हो रहा है उसे कुचलने के लिये अनेक दमनकारी तरीके आपनाये जा रहे हैं लेकिन उससे वास्तविक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आज सारे देश में एक असन्तोष की लहर दौड़ रही है। सवालों को सड़कों पर लाकर हल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक छोटासा काण्ड, एक साधारण सा आन्दोलन हिंसात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। यह खेद का विषय है कि गृह मंत्रालय इस सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य का पालन करने में सफल नहीं हुआ है। यदि जनता की व्यथा का निराकरण करने में बिलम्ब होगा, यदि असन्तोष को एकत्र होने दिया जायेगा, यदि उचित मांगों पर तुरन्त कार्यवाही नहीं की जायेगी तो फिर जनता का असन्तोष ऐसा रूप लेकर फूटेगा जिसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है और जिसमें लोकतांत्रिक प्रणाली के लिये भी संकट पैदा हो सकता है। इसके लिये शासन के रवैये में बुनियादी परिवर्तन आवश्यक है।

कल इस विवाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय उर्दू को दूसरी राज भाषा बनाने, कई भागों में हुये दुर्भाग्यपूर्ण साम्प्रदायिक दंगों की काफी चर्चा की गई। मेरी पार्टी का नाम भी घसीट कर हम पर अनर्गल आरोप लगाये गये। हमारा निश्चय मत है कि जहां साम्प्रदायिक दंगा होता है वहां दंगा करने वाले फिर वे किसी भी समाज के व्यक्ति हों उनका दृढ़ता से दमन होना चाहिये। दंगे में जिनकी क्षति होती है उनको पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिये। लेकिन दंगों के बुनियादी कारणों में भी जाना आवश्यक है। हम आशा करते थे कि पाकिस्तान का विभाजन हो गया, मजहब के आधार पर बना पाकिस्तान एक नहीं रह सका, स्वाधीन बंगलादेश का अभिर्भाव हुआ, अब भारत का भी वातावरण बदलेगा और मजहब के आधार पर संघर्ष या विभेसाधिकारों की मांग नहीं होगी लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के विभाजन और बंगलादेश की मुक्ति से हमने कोई पाठ नहीं सीखा। आज भी मजहब के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अभी दिल्ली में 10–11 मार्च, को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें भाषण दिये गये। एक व्यक्ति ने कहा, मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं :

> "जिस इन्दिरा को हम तख्त पर बिठा सकते हैं उसे हम तख्ते पर भी बिठा सकते हैं"।

यह भी कहा गया :

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुये कातिल में है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में कहा गया है कि उनके नाम में "ख" भी है और "र" भी है और यदि दोनों को मिला दें तो "खर" बनता है। उनके विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया गया। श्री नूरुल हसन साहब को नमक हराम कहा गया। ... (व्यवधान) और वहां पर जाने वालों में शमीम साहब के नेता शेख अब्दुल्ला भी थे।

श्री एस० ए० शमीम : (श्रीनगर) : आपके बांई तरफ वाले श्री पीलू मोदी भी थे ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं अपने दायें बायें वालों से कोई मतलब नहीं रखता ।

श्री एस० ए० शमीम : मेरा भी कोई नेता नहीं है, मैं अपना नेता आप हूं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप अपने नेता भी हैं और अपने अनुयायी भी आप ही हैं । न इनका कोई नेता है और न इनके पीछे चलने वाला कोई है ।

श्री एस० ए० शमीम : इसीलिये दयानतदारी से बात करता हूं ।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : डा० फरीदी ने कहा है कि हम जनसंघ से कोआपरेशन लेंग । (व्यवधान) ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : डा० फरीदी ने यह भी कहा है कि जनसंघ कोआपरेशन के लिये बिल्कुल तैयार नहीं है (व्यवधान) . . .

मैं जानना चाहता हूं कि आज देश का साम्प्रदायिक वातावरण क्यों बिगड़ रहा है ? आज मुस्लिम समाज में से एक वर्ग ऐसा क्यों निकल रहा है जो बम्बई में खड़े होकर कहता है कि हम बन्दे मातरम कहने के लिये तयार नहीं हैं ? बंदे मातरम इस्लाम का विरोधी नहीं है । क्या इस्लाम को मानने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो इस देश की धरती पर, इस देश की पाक जमीन पर सिर नहीं टेकते हैं ?

श्री एस० ए० शमीम : खुदा के लिये ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मगर सिर जमीन पर टेका जाता है । इस जमीन से पैदा हुआ अन्न हम खाते हैं । यह जमीन आखिरी क्षणों में हमको अपनी बाहों में लपेट लेती है । क्या दुनियां के और देशों में राष्ट्र गीत नहीं हैं ?

श्री एस० ए० शमीम : राष्ट्रगीत तो जनगणमन है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं यही गलतफहमी आपको दूर करना चाहता हूं ।

श्री एस० ए० शमीम : कर लीजिये जितनी जल्दी हो सके ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कल भी आपने यही बात कही थी । मेरे पास संविधान परिषद की कार्यवाही है ।

यह अध्यक्ष महोदय का दिया गया वक्तव्य है :

"24.1-1950: Statement regarding National Anthem.

MR. PRESIDENT: There is one matter which has been pending for discussion, namely, the question of the National Anthem. At one time it was thought that the matter might be brought before the House and a decision taken by the House by way of a Resolution. It has been said that instead of taking a formal decision by means of a resolution it is better if I make a statement with regard to the National Anthem. Accordingly I make this statement.

The composition consisting of the words music known as Jana Gana Man is the National Anthem of India subject to such alterations in one word as the Government may authorise as the occasion arises and the song Vande Matharam which has played a historic part in the struggle for Indian freedom shall be honoured equally with Jana Gana Man and

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

shall have equal status with it.... (Applause) I hope this will satisfy the Members."

अध्यक्ष महोदय, बम्बई में झगड़ा प्रारम्भ हुआ जब उर्दू मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने 26 जनवरी को बंदे मातरम कहे जाने पर खड़े होने से इन्कार कर दिया।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : जब्र किया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जब्र किसी पर नहीं किया जाता है।

श्री एस० ए० शमीम : कहा गया कि जो नहीं पढ़ेगा उसको मार डालेंगे। स्कूल बन्द कर दिया गया ... (व्यवधान)।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष जी, क्या कोई कल्पना कर सकता था कि देश के .....(व्यवधान)।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Mr. Speaker, Sir, I committed a mistake. Instead of 'President', I said 'Jawaharlal Nehru'. I am requesting Shri Vajpayee to make that correction. When I quoted this Resolution, by mistake, instead of 'President' I said 'Jawaharlal Nehru'.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: अध्यक्ष जी, क्या किसी ने यह कल्पना की थी .... (व्यवधान)।

SHRI R. S. PANDEY (Rajnandgaon): *Vande Mataram* is the prayer of the motherland.

SHRI S. A. SHAMIM: There are other songs also.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Whether you agree or disagree, this is a democratic way of saying.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : Nobody can be allowed to disagree on such issues.

कल यह कहेंगे कि तिरंगा झंडा है मगर हम तिरंगे झंडे के सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, तिरंगे के सामने नहीं झुकेंगें। हिन्दुतान में रहने वाले हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना पड़ेगा .... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पट्रीआटिज्म के अर्थ अलग अलग नहीं होते हैं।

श्री एस० ए० शमीम : होते हैं अलग अलग। आपका उसूल है कि मुसलमान पैट्रियाट नहीं होते। जब कि हमारा उसूल है कि हिन्दुस्तान में रहने वाला हर पैट्रियाट है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अगर हमारा यह उसूल होता अध्यक्ष महोदय, तो पंडित प्रेम नाथ डोगरा की सीट पर जम्मू में जहां दो फीसदी मुसलमान हैं हम एक मुसलमान को चुन कर जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में नहीं भेजते। वहां कांग्रेस का एक केडीडिट हिन्दू खड़ा था और यह प्रचार किया गया कि जनसंघ ने हिन्दू की सीट मुसलमान को दे दी, फिर भी लोगों ने हमको वोट दिया है।

श्री एस० ए० शमीम : ऐसे बहुत से हिन्दू मुस्लिम लीग में भी पाये जायेंगे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हिन्दू मुस्लिम लीग में पाये जायेंगे ? और आप भारतीय जनसंघ में पाये जायेंगे।

श्री एस० ए० शमीम : खुदा मुझे उससे पहले मौत दे दे।

अध्यक्ष महोदय : अरे, आप इतना गरम क्यों हो रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि वंदे मातरम् के सवाल को लेकर जो दुर्भाग्यपूर्ण विवाद खड़ा हुआ है इसको समाप्त किया जाये । .... (**व्यवधान**) मुस्लिम लीग ने इसे खड़ा किया है । और अध्यक्ष महोदय, यह लीग तक ही सीमित नहीं रहा, बम्बई कारपोरेशन के कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे, श्री खंडवानी, उन्होंने भी उनका साथ दिया । अब प्रधान मंत्री कहती हैं कि बम्बई कारपोरेशन में सम्प्रदायवादी शक्तियां जीत गई हैं जिसका परिणाम हो रहा है वहां दंगे हो रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग के साथ केरल में सरकार बना कर किसने साम्प्रदायिकता को जिलाया है ? आजाद हिन्दुस्तान में मुस्लिम लीग की जरूरत क्या है ? पार्टियां ऐसी होनी चाहियें जिनके दरवाजे सबके लिये खुले हों । भारत का हर नागरिक हर पार्टी में जा सके । लेकिन मुस्लिम लीग की निन्दा करने के बजाय मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनायी जा रही है । वही मुस्लिम लीग जब बंदे मातरम् का विरोध करके बम्बई में जीतती है तो प्रधान मंत्री को रंज होता है । जो बीज आपने बोये हैं उनके कडवे फल आपको चखना पड़ेंगे । मैं यह भी कहता हूं कि साम्प्रदायिकता एक दुधारी तलवार की तरह से है मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन दे कर आप दूसरे वर्ग की साम्प्रदायिकता से नहीं लड़ सकते ।

अब अलीगढ़ का मामला लाया जा रहा है, । अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अलीगढ़ को लेकर यह क्या बवाल मचाया जा रहा है सारे देश में ? कहा जा रहा है कि अलीगढ़ युनिवर्सिटी का मुस्लिम कैरेक्टर सुरक्षित रहना चाहिये । क्या मतलब है मुस्लिम कैरेक्टर का ? मुसलमान केवल हिन्दुस्तान में नहीं हैं, मुसलमान बांगला देश में हैं, मुसलमान दुनियां के और देशों में हैं । क्या उन सबके विश्व-विद्यालयों का कैरेक्टर एक ही होगा ? विश्वविद्यालय जिस मिट्टी पर बना है उस मिट्टी का रंग विश्वविद्यालय पर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा ? विश्वविद्यालय जिस समाज में काम करेगा उस समाज की आशा और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगा या नहीं करेगा ?

हां, कोई कहे कि वहां इस्लाम की पढ़ाई होनी चाहिये तो मुझे आपत्ति नहीं होगी । उस का प्रबन्ध है कहां । मुस्लिम थियोलोजी का अगर पठन पाठन का प्रबन्ध आवश्यक है तो वह भी किया जा सकता है । लेकिन उसे केवल माइनारिटी का इंस्टीट्यूटशन बनाया जाय, यह स्वीकार नहीं होगा । मेरा निवेदन है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मुस्लिम कैरेक्टर का सवाल पैदा नहीं होता । हिन्दुस्तान में हर एक विश्वविद्यालय स्वरूप में भारतीय होना चाहिये । यह बात जितनी अलीगढ पर लागू होती है उतनी हिन्दू विश्वविद्यालय पर लागू होती है । हर विश्वविद्यालय का स्वरूप भारतीय होना चाहिये । अलग अलग धर्मों, दर्शनों के पठन पाठन का इन्तजाम करें, इसमें कोई विरोध को आवश्यकता नहीं है ।

हां, विश्वविद्यालय का एक जो पहलू है उससे मेरा मतभेद है और वह यह है कि हर विश्वविद्यालय में सरकार अपना अधिकार बढ़ाने जा रही है .... (**व्यवधान**) ।

श्री एस० ए० शमीम : माइनारिटी राइट्स क्या होते हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : माइनारिटी राइट्स कुछ नहीं होते हैं । माइनारिटी राइटस होते हैं लैंगुएज के बारे में, माइनारिटी राइट्स होते हैं इस्लाम के अध्ययन के बारे में । माइनारिटी राइटस यह नहीं कहते कि यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान में ऐसी बनेगी जिस में सारे प्रोफ़ेसर मुसलमान होंगे । इस सदन में

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

खुली चर्चा हो कि मुस्लिम कैरेक्टर का मतलब क्या है । .....

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : मगर अलीगढ़ में यही सपोर्ट करते हैं ।

श्री इसहाक सम्भली : आप तो उसके लाइफ़ मेम्बर होने जा रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम सपोर्ट नहीं करते हैं । अध्यक्ष जी, यह मौलाना साहब ऐसे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में भी हैं, जमायेतुल-उलेमा में भी हैं । यह दोनों तरफ़ हैं । कम्युनिस्ट पार्टी इस्लाम नहीं मानती । मजहब नहीं मानती मगर मौलाना साहब जमायतुलउलेमा के मौलाना भी हैं । यह दोनों रंग खेल रहे हैं ।

श्री इसहाक सम्भली : आपको बेचैनी क्यों है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे बेचैनी नहीं है । मैं आपका असली रंग सामने रख रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालयों का लोकतन्त्रीकरण होना चाहिये । अलीगढ़ में अगर ऐकेडेमिक काउन्सिल नौमीनेटेड है तो गलत है ।

श्री बी० पी० मौर्या (हापुड़) : अलीगढ़ का आखिर में होना चाहिये, पहले औरों का होना चाहिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : देखिये आगे, पीछे नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं कि बनारस विश्वविद्यालय काविधेयक लाओ । आप जानते हैं कि हम मांग कर रहेहैं कि उसको लाइये । ऐकेडेमिक काउन्सिल में नौमिनेटे मेम्बर ज्यादा हैं ही, ऐग्जीक्यूटिव काउन्सिल में नामजद मेम्बर ज्यादा हों, विजिटर को असाधारण अधिकार हों हम इस के हक में नहीं हैं । विश्वविद्यालयों का लोकतन्त्रीकरण हो और वह सब विश्वविद्यालयों पर लागू किया जाय । जो अलीगढ़ की वकालत कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि माइनारिटी कैरेक्टर या मुस्लिम कैरेक्टर की बात मत करिये आटोनामी की बात करिये । यह आप नहीं कर रहे हैं ।

अभी श्री नुरुलहसन अलीगढ़ यनिवर्सिटी में गये थे, मगर अलीगढ़ युनिवर्सिटी में नुरुल हसन साहब को बोलने नहीं दिया गया । उनको खाना तक नहीं खाने दिया गया, उनकी कार पर जूते मारे गये । क्या मतभेद को प्रकट करने का यही तरीका है ? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जो गलीगढ़ का मामला उठा रहे हैं वह इस बारे में मुस्लिम कैरेक्टर की व्याख्या करें । यह सदन और यह देश अपना आखिरी तौर पर इस बारे में दिमाग बना ले ।

दूसरी चीज है उर्दू के बारे में । कल मौलाना इसहाक सम्भली ने कहा कि आज जनसंघ भी चुनाव जीतने के लिये उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनाने का समर्थन कर रहा है । यह ईउन्होंने कहां से सुना है ?

श्री इसहाक सम्भली : आपने टाउन हाल, मुरादाबाद, में यह कहा ।

श्री एस० ए० शमीम : और 25 तारीख को सात बजे शाम ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो अखबारी में खबर छपी थी वह टाउन हाल की नहीं थी । वह खबर यह थी कि मैंने वर्कर्स मीटिंग में कहा । मैंने उसका खण्डन किया ।

13.00 hrs.

खंडन इस बात का किया है कि मैं उर्दू को दूसरी राज भाषा बनाने के हक में हूं। मैं मानता हू कि उर्दू भारत में पदा हुई है उर्दू भारत की भाषा है, उर्दू फलनी और फूलनी चाहिये। जम्मू और काश्मीर में उर्दू राजभाषा के स्थान पर भी प्रतिष्ठित है। किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। लेकिन हम यह नही मानते हैं कि उर्दू सारे मुसलमानों की भाषा है। हम यह भी नहीं मानते कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है। उर्दू पढ़ने पढ़ाने की पूरी सुविधा दी जाये, उर्दू में कोई पुस्तक लिखे उसको प्रोत्साहन दिया जाये, उर्दू में अगर दरख्वास्तें आयें तो जहां तक सम्भव हो उनका जवाब भी उर्दू में देने की कोशिश होनी चाहिये। और यह बात केवल उर्दू पर लागू नही होती है। हमारे संविधान में लिखा है कि जहां पैटीशन दी जाये तो शासन द्वारा इंतजाम करने की कोशिश होनी चाहिये कि उसी में जवाब दिया जाये। अगर उर्दू के माध्यम से कोई पढ़ना चाहता है तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

लेकिन उर्दू को राजभाषा बनाने का सवाल इतना सरल सवाल नहीं है। दूसरी राज भाषा बनाने की मांग के पीछे साम्प्रदायिक कारण हैं, अलगाव की राजनीति काम कर रही है। आपको दूसरी राज भाषा बनाने के लिये एक नियम बनाना पड़ेगा। किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोलने वाले कितने फीसदी है तब वह भाषा राज भाषा बनाई जाये, यह आपको तय करना पड़ेगा। केवल उर्दू का सवाल नहीं है। असम में बंगला का भी सवाल है, पंजाब में हिन्दी का भी सवाल है। क्या आप उर्दू के लिये एक नियम बना देंगे और दूसरी भाषाओं के लिये दूसरे नियम? यह नहीं हो सकता है।

मेरा निवेदन है कि उर्दू को जिन कारणों से आन्दोलन का विषय बनाया जा रहा है, उस म उर्दू भाषा के विकास की भावना नहीं है। उर्दू के झंडे के तले सब मुसलमानों को ए कत्रित करने और विभाजन के पूर्व की मुस्लिम लीगी राजनीति को पुनरुज्जीवित करने की भावना काम कर रही है। इससे हमारा मतभेद है। हमारा कहना यह है कि अगर आप राज भाषा बनाने का निर्णय करेंगे तो हर कार्यालय में छोटा पाकिस्तान बन जायेगा।

आखिर उत्तर प्रदेश में क्या सभी मुसलमान उर्दू बोलते हैं? क्या ब्रज में रहने वाला मुसलमान ब्रज भाषा नहीं बोलता है? क्या अवध में रहने वाला मुसलमान अवधी नहीं बोलता है? मगर मुस्लिम लीग के जो सदस्य केरल मे चुनकर आये हैं, जो उर्दू बोल नहीं सकते हैं, वे उर्दू की वकालात कर रहे हैं और समझते हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। यही बात जिन्ना ने कही थी कि हिन्दू और मुसलमान अलग हैं, हिन्दुओं की भाषा अलग है, मुसलमानों की भाषा अलग है। मेरा निवेदन है कि यह दृष्टिकोण गलत है। इस दृष्टिकोण का आप परित्याग कर दें, फिर उर्दू के लिये शासन में जो सुविधायें चाहियें, मिलेंगी। लेकिन उर्दू को राजनीति का हथियार न बनायें।

मैं कांग्रेसी मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। चुनावों में वोटों की लालसा स्वाभाविक है। प्रत्येक दल इसके लिये प्रयत्नशील है। लेकिन वोट से बड़ा देश हुआ करता है ... (**इंटरप्शन**) फरीदी से पिछले चुनाव से पहले जो आपने गुप्त समझौता किया था उसी का नतीजा सामने आ रहा है। जो पर्दे के पीछे वायदे किये गये हैं वे पूरे नहीं किये गये, इसीलिये आज फरीदी जी बिगड़ रहे हैं। मेरा कहना है कि मुसलमानों और उर्दू के सवाल को आप पार्टी का सवाल न बनायें। सब दल मिल कर बैठें और इसके सम्बध में एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करें। नहीं तो पाकिस्तान बट गया, बंगला देश स्वाधीन हो गया और

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हिन्दुस्तान में मुस्लिम लीग बढ़ रही है, हिन्दुस्तान में फिरकापरस्ती बढ़ रही है। दीक्षित जी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। दीक्षित जी आज उस पद पर विराजमान हैं जिन पर कभी सरदार पटेल बैठते थे। उन्हें कुछ सरदार पटेल से प्रेरणा लेनी होगी, उन्हें राजा जी की राजनीतिक विलक्षणता से भी कुछ सीखना होगा। उन्हें पन्त जी के धैर्य और प्रशासन क्षमता का भी अनुकरण करना होगा। संकट की इस घड़ी में अगर गृह मंत्री के रूप में वह राष्ट्र की नौका को सीधा भंवर से निकाल कर सुरक्षा और शान्ति के तट तक पहुंचा सके तब गृह मंत्री का पद सफल हो सकता है अन्यथा आने वाले संकटकाल में वह गृह मंत्रालय को तो भंवर में ले ही बैठेंगे लेकिन साथ ही देश के लिये भी ऐसी कठिनाई पैदा करेंगे जो लोकतंत्र को भी खतरे में डाल सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो आपसे उर्दू बोलने की इजाजत है न कभी कभी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उर्दू मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। उर्दू की शायरी का तो मैं भी बहुत कायल हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो भी गैर शादीशुदा होता है वह उर्दू की शायरी पर फरेफता होता ही है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मुझे मौका दिया जाये। मैं कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, जब आपको मौका मिले आप कर लेना।

श्री दरबारा सिंह : (होशियारपुर) : कल से होम मिनिस्ट्री पर बहस हो रही है। कुछ दोस्तों ने काफी गम्भीर सवाल उठाये हैं। डेमोक्रेसी में बहुत मुश्किल है। किसी की आवाज को दबाना बहुत मुश्किल है। कानून के अन्दर रह कर अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। लेकिन किसी को लम्बी जबान करके बोलने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिये, मैं ऐसा भी मानता हूं। यह बहुत बड़ा और अहम महकमा है। एक घर में बैठ कर तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करना इस विभाग की जिम्मेदारी है। हम नये जमाने में से गुजर रहे हैं। जो ट्रेडीशनल चीजें चली आ रही थीं उनमें चेंजिज आ रही हैं, तबदीलियां आ रही हैं। उसके कारण बहुत से सवाल उठ खड़े हुये हैं। हड़तालें होती हैं, नारेबाजी होती है, मुजाहरे होते हैं, भूख हड़तालें होती हैं। लोगों की मांगें बढ़ी हैं। जमाने के साथ साथ एक नया रंग आया है और आयेगा। इकोनोमिक ग्रोथ के साथ साथ नई प्राब्लेम्स भी सामने आ रही हैं। उनको भी इस मिनिस्ट्री को टैकल करना है। ग्रुप राइबेलरीज की देखभाल भी इनको करनी पड़ती है। रावट्स होते हैं, कम्युनल रायट्स होते हैं उनको भी इसको रोकना होता है और उस पर मैं बाद में आऊंगा यहां क्या कहते हैं और लोगों में जाकर क्या करते और कहते हैं यह सब मैं बाद में अर्ज करूंगा। रायट्स कोई बाहर वाले आ कर यहां नहीं करते हैं। कभी हिन्दू-मुस्लिम का सवाल पैदा किया जाता है और कांग्रेस तो इसको करती नहीं है.....

एक माननीय सदस्य : वही करती है।

श्री दरबारा सिंह : चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने आपका नाम भी नहीं लिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दाढ़ी नहीं है तो तिनका कहां से होगा

श्री दरबारा सिंह : सर में ले लें।

अध्यक्ष महोदय : मूंछ में कह दें।

श्री दरबारा सिंह : मूंछ भी नहीं हैं।

ग्रुप रायबेलरीज जो होती है, रायट्स जो होते हैं, कम्युनल रायट्स जो होते हैं और

जो प्रोवोकेट करते हैं, उस सबकी रोकथाम करना भी इस मिनिस्ट्री का जिम्मा है। बहुत मुश्किल काम इसके जिम्मे है। यह कहा जाता है कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। बाजपेयी जी ने भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि पिछले जो गृह मंत्री हुये हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन सब चीजों को और इस मिनिस्ट्री को सम्भाला है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वे बहुत बड़े थे और उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन आज भी इनके सपूत जो रहे हैं आप बेफिक्र रहें कि वे भी उसको अच्छी तरह से सम्भालेंगे। मैं कारण जो है उनको अर्ज करना चाहता हूं। लैण्ड सिस्टिम में एक चेंज आई है। सरकार एक लैजिस्लेशन लाई है जमीन की हद मुकर्रर करने के लिये। इससे भी कुछ जुर्म बढ़े हैं, लड़ाई झगड़े बढ़े हैं। जिसको सरपलस जमीन मिलनी है, उसको दबाया जा रहा है। ये झगड़े बढ़ेंगे। नया सिस्टम जो हम ला रहे हैं, समाजवाद की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसी चीजों का आना लाजिमी है।

हमारे देश में पापुलेशन तेजी से बढ़ रही है और प्राडक्शन कम हो रही है। पापुलेशन बढ़ने के नतायज हमारे सामने हैं। 1912 में दिल्ली की आबादी एक लाख के करीब थी, लेकिन अब वह बीस-तीस गुना ज्यादा हो गई है। इसलिए दिल्ली की प्राबलम्ज भी बढ़ गई हैं और यहां जुर्म भी बढ़ गये हैं। इस तरफ़ पूरी तवज्जुह देना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है।

बार्डर सिक्युरिटी फ़ोर्स भी इस मंत्रालय के मातहत है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई के वक्त उस ने बार्डर पर बहुत अच्छा काम किया। शायद कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी जाकर बार्डर नहीं देखा है। लेकिन हम बार्डर से मुताल्लिका हैं और इसलिए हमको पता है कि मिलिटरी के पहुंचने तक उन्होंने बड़ी जांफ़िशानी से लड़ाई में हिस्सा लिया और देश के लिए अपना खून दिया। सरकार ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है और उनके बेनिफ़िट के लिए लाखों रुपये दिये हैं।

कुछ लोगों ने सी०आर०पी० के खिलाफ़ भी आवाज़ उठाई है। सी०आर०पी० के साठ बैटेलियन इसी लिए खड़े किये गये हैं कि वे देश में ला एंड आर्डर कायम रखने में सरकार की मदद करें और जहां कहीं उपद्रव हों, वहां अमन बरकरार रखें।

इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि 1972 के इलैक्शन बहुत हमवार्गी से और निहायत अच्छे ढंग से हुए और इतने बड़े देश में बहुत कम वाकयात हुए। यह भी गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी और उसने इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया है।

इससे ज्यादा सताइश के काबिल और कोई बात नहीं है कि होम मिनिस्ट्री ने फ्रीडम फ़ाइटर्ज की मदद करने का काम अपने हाथ में लिया है। जो लोग इस देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, जिन्होंने इस मकसद को हासिल करने के लिए अपना खून और अपनी जवानी दे दी, जो फांसी के तख़्ते पर चढ़े, जिन्होंने अपनी सारी ज़िन्दगी देश की आज़ादी के लिए न्योछावर कर दी, जिन्होंने दस, पंद्रह और बीस साल की लम्बी कैदें काटीं और जिनके ख़ानदान तबाह हो गये, उन लोगों या उनके बीवी-बच्चों के लिए सरकार ने पेंन्शनें मुकर्रर की हैं। जिन लोगों ने उस वक्त अपनी जवानी में भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, उसकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया और जेल नहीं गये, उनको इन फ्रीडम फ़ाइटर्ज की ख़िदमात का शायद एहसास न हो, लेकिन हमें पूरा एहसास है। स्पीकर साहब, आप तो उस फ़ाइट में हिस्सा लेने वालों की सफ़-अव्वल में थे। आपको पता है कि उस ज़माने में ग़रीब आदमियों ने क्या कुर्बानियां दीं और किन दुश्वारियों का सामना किया और देश के लिए आज़ादी हासिल की। इस सरकार

श्री बरबारा सिंह :

ने उन लोगों को पेन्शन देने का इन्तज़ाम किया है, इससे ज्यादा बड़ा काम अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है, और अगर किया होगा, तो इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया होगा ।

मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस काम को तेज़ करना चाहिए । उनमें से कुछ लोग तो करीबुल–मर्ग हैं, उनकी ज़िन्दगी के आख़िरी अयाम हैं और कुछ लोग तो मर भी चुके हैं । आज उन लोगों और उनके बीवी-बच्चों की मदद करने की ज़रूरत है, ताकि वे अपना गुज़ारा कर सकें । उनके स्पेशल केस बना कर फ़ौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए । मैं जानता हूं कि सरकार ने यह फ़ैसला किया है कि 15 अगस्त तक तमाम एप्लिकेशन्ज़ को सार्ट आउट कर के सब लोगों को पेन्शन दे दी जायेगी और एक साल का बकाया भी दिया जायेगा । यह एक काबिले-तारीफ़ काम है । इसका नतीजा यह होगा कि वे फिर से अपनी ज़िन्दगी शुरू कर सकेंगे और उन विद्दतों का मुकाबला कर सकेंगे, जो इस वक्त मुल्क में सिर उठा रही हैं । इस काम के लिए होम मिनिस्ट्री की सताइश करना ज़रूरी है ।

जहां तक क्राइम का ताल्लुक है, अब क्राइम करने वाले भी नये ढंग इस्तेमाल करते हैं । अब कोई पैदल जाकर क्राइम नहीं करता है, बल्कि अब कारों में जा कर क्राइम किये जाते हैं । अब क्राइम करने वालों के पास भी जदीद असलहा है और वे भी नये साइंटिफ़िक ढंग से काम करते हैं । इसलिए उन लोगों का मुकाबला करने के लिए पुलिस को भी नये हालात के मुताबिक आर्गनाज़ करना चाहिए और उस के लिए और ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर बनाये जाने चाहिए । जिस हालत में से हम गुज़र रहे हैं, उस में पुलिस को इनटेलिजेंस और क्रिमिनालोजी के फ़ील्ड्ज़ में नई साइंटि-एक ट्रेनिंग देना निहायत ज़रूरी है ।

यह ठीक है कि सरकार स्मगलिंग की रोक-थाम कर रही है । लेकिन इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स को खींचने की ज़रूरत है । स्मगलिंग ज्यादातर ओपियम, पोस्त, सोने और करन्सी की होती है । सब से ज्यादा खतरनाक और एन्टी-नैशनल एक्टिविटीज़ उन इन्टर-नैशनल रैकेटियर्ज़ की हैं, जो करन्सी की स्मगलिंग करते हैं । यह बड़ा भारी जुर्म है । देश का करोड़ों रुपया इस ढंग से ज़ाया किया जा रहा है । उन लोगों की मरम्मत करने की ज़रूरत है ।

इसके अलावा इल्लिमिट डिस्टीलेशन करके, घर में शराब बना कर, उसको बेचा जाता है । उन लोगों का ज़ोनल सिस्टम बना हुआ है । उनके बड़े बड़े सप्लाई के सेंटर हैं । वहां से वह शराब ज़ोन्ज़ को सप्लाई की जाती है और फिर आम आदमी को बेची जाती है । आज पकड़ा वह शख़्स जाता है, जिसके पास एक बोतल होती है, जब कि वह नहीं पकड़ा जाता है, जिसके पास हज़ारों बोतलें होती हैं । इस तरफ़ ध्यान देने की ज़रूरत है । मार्फ़िया के इन्जक्शन लगाने का काम भी चल रहा है । शराब का नशा तेज़ करने के लिए उसमें बहुत ज़हरीली चीजें डाली जाती हैं । यह ठीक है कि बार्डर पर जो सोने की स्मगलिंग होती है, सरकार उसकी तरफ़ ध्यान दे रही होगी, लेकिन इस सिलसिले में और ज्यादा सख़्ती से पहरा देने की ज़रूरत है । सरकार के पास ऐसी फ़ोर्स है, जो इसको रोक सकती है ।

आज हमारे मुल्क में पोस्त और ओपियम वगैरह की एडिक्शन को रोकने की ज़रूरत है । हमारे समाज को इससे बहुत नुक्सान हो रहा है । अगर हमारे लोगों की जान कायम रहे, लेकिन उनका शरीर तंदुरुस्त न हो, तो फिर देश की तरक्की कैसे हो सकती है ? वे पोस्त पी कर, अफ़ीम खा कर और शराब पी कर एक अच्छी नेशन नहीं बना सकते हैं ।

खाविन्द और बीवी का झगड़ा हो या नौकर और मालिक का झगड़ा हो, ये सब खुराफ़ात सरकार को तय करनी पड़ती हैं। मन्दिर और मस्जिद का झगड़ा हो, दो सूबों का आपस में झगड़ा हो, रायटस हों या कम्युनल फ़ीलिंग्ज को उभारा जाता हो, तो सरकार को कुछ प्रीकाशनरी मेज़र्ज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र्ज़ लेने होते हैं। यह आसान बात नहीं है। सब से कठिन काम इस मिनिस्ट्री का है। बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेकर मरने तक इसका इंतजाम, इसका दखल जरूरी है वहां। जिन हालात में यह चल रही है आप इसे एप्रिशिएट करेंगे। सारे झगड़े जो हैं, बेशक रुपये का हो, वह भी इनके पास आयेगा, जमीन का हो, तो भी किसी न किसी सूरत में इनके पास आयेगा, कम्युनल रायटस हों, धर्म के नाम पर, वे भी इनके पास आयेंगे। बड़े चुस्त अलफाज में वाजपेयी जी ने इन रायटस के बारे में कहा है। बहुत अच्छ अलफाज हैं। लेकिन अफसोस है कि उसको वह अमल में नहीं लाते। अगर लायें तो बहुत अच्छा होगा।

उर्दू की वह सपोर्ट करते हैं लेकिन कहते हैं कि हिन्दू के लिए नहीं होनी चाहिए, मुसलमान के लिए होनी चाहिए। राज भाषा या दूसरी भाषा के रूप में कहीं उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। जब वह यह कहते हैं कि उर्दू भारत की जबान है तो फिर मुसलमान के नाम पर इस जबान को क्यों लगाते हैं। इसका विरोध इसीलिए हो रहा है कि उर्दू जो है उसके लिए उनके दिल में कुछ और है और यह कहा उन्होंने बहुत चुस्ती से और बहुत समझदारी से जब बीच में उन्होंने यह कहा कि इससे आप पाकिस्तान जगह जगह देखेंगे। यही बात है जो आप यू०पी० में ले जा कर कहना चाहते हैं। लेकिन आप भूलें नहीं कि वे हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं और इसी धरती पर पैदा हुए हैं, कहीं बाहर से आ कर नहीं बसे हैं, इसलिए उनका भी उतना ही हक है माइनोरिटी के नाते जितना और किसी का है। आप माइनोरिटी में यकीन नहीं करते, मत करें लेकिन माइनोरिटी है और कायम है। उसको अधिकार देने होंगे और उनके लिए कुछ न कुछ करना होगा ताकि वे उस मतह पर आ सकें जहां उनकी इनफीरियारिटी कम्प्लेक्स निकल पाये ताकि वे देश के तरक्की के कामों में अपना हिस्सा ले सकें और कह सकें कि हम भी इस देश में हिस्सेदार हैं, हम भी इस समाज में रहने वाले हैं। अगर यह नहीं करेंगे तो आप उनको दूर फैंकेंगे और दूर फेंक कर जो नतायज हमने देखें हैं आपके सामने हैं। कहते हैं कि तकसीम हुई, पाकिस्तान बना, हमने उससे सबक नहीं सीखा। किसने नहीं सबक सीखा? हमने तो बहुत कुछ सीखा है। आप तो बहुत दूर बैठे हुए हैं। हम रोज सीखते हैं। पाकिस्तान के बोर्डर पर बैठने वालों को पता है कि क्या मजे हमें इसके मिलते हैं। आपको समझना चाहिए कि अन्दर आपके कुछ और है और बोलने आप कुछ और हैं। आपकी अन्दरूनी तसवीर एक्सरे में नहीं आती है, इसलिए आप बचे हुए हैं। जो आप कहते हैं उसी पर चलें तो ये जो झगड़ें रोज होते हैं वे न हों। कहीं यू० पी० में झगड़ा हो गया, कहीं मध्य प्रदेश में हो गया, कहीं रायटस हो गये। ये रायटस कौन कराता है और इनको करा कर खुद जो चोर है वह दूसरे पर हाथ रखता है और कहता है कि यह चोर है। जहां तक कांग्रेस का तालुक है इस पार्टी के लोगों ने अपनी जान दी है, माइनोरिटीज को बचाने के लिए और हिन्दुस्तान में नेशनलिज्म को कायम करने की कोशिश की है। हमने कभी यह नहीं किया कि फिरकेदारी की आवाज उठा कर एक दूसरे को बांटें। फिर वह नेशनलिज्म क्या हुआ? कांग्रेस का फिलसफा यही है, जो बुनियादी चीज है वह इसी पर खड़ी है कि हम इसमें यकीन करते हैं क नेशनलिज्म ही हमें आगे ले जा सकता है। इसलिए हम सब को साथ ले कर चलते हैं। माइनोरिटी के लिए वाजपेयी जी का यह कहना कि माइनोरिटीज कहां होती हैं, क्या होती हैं, आप होते तो आपको ले चलता। आप एक स्वीपिंग रिमार्क करके इससे बच कर

श्री दरबारा सिंह :

निकल नहीं सकते । हम माइनोरिटीज की खुद यहां हाउस में नामजद करते हैं और वे आपके साथ बैठ कर अपोजीशन में रोज कांग्रेस की मुखालफत करती है । फिर भी सारी माइनोरिटीज का ध्यान कांग्रेस को है ।

पालिटिकल बातों के बारे में उन्होंने कहा कि आंध्र में, असम में यह हुआ । झगड़े जहां होंगे वहां पुलिस पहुंचेगी, वहां उसे इंतजाम करना पड़ेगा और इंतजाम में गोली चली इसमें कोई शक नहीं । लेकिन गोली चलवाने वाले पीछे होते हैं और मरने वाले और होते हैं । आप अपना अंदाजा कीजिये कि आप क्या कर रहे हैं । मुझे उस तरफ न ले जाइये जहां मुझे आपको बहुत कुछ कहना पड़े ।

एंटी करप्शन मेजर्स सरकार ले रही है, इससे शक नहीं । लेकिन हमारी बाडी पालिटिक में यह बात आ गई है । मैं किसी सूबे की बात नहीं करता । जो बोलते हैं वे अपने सूबे में झांक कर देख लें । करप्शन यह नहीं कि सरकारी सतह पर ही है । यह समाज में एक बहुत भारी बुराई है जिस को आपको काटना होगा । बुराई किसी एक वजीर के खिलाफ हो, ऐसी बात नहीं है । आप देखें कि जहां किसी को आसानी से रुपया दस्तयाब हो सकता है, उसको हासिल करने की वह कोशिश करता है । मैं बड़े वाजह अलफाज में कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी की वर्किंग की ढील से ऐसा हो रहा है । अगर तेजी से काम हो, फाइल पर फाइल जमी न रहे और बीसियों हाथों से घूम कर न आये तो बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है और काम वक्त पर और तेजी से चल सकता है । वरना यह करप्शन घर कर रहा है । इसको आप तोड़िए और स्पीड अप करिए इस बात को कि वह लोग अपनी फाइलों का काम जल्दी से करें । साथ ही जितनी रुकावटें हैं उनको दूर करिए । क्योंकि जिसके पास काला धन है वह किसी न किसी ढंग से पहुंचता है और आप के नेक काम करने वालों पर भी धब्बा लगाने का काम करता है । वह पहुंचता है उस जगह जहां उसको जगह मिलती है, जहां उसको गुंजाइश मिलती है, जहां उसको पैसा देने का मौका नजर आता है और अपना काम करवाता है । ये जो अपने काम करवाते हैं वह वही बड़े बड़े लोग हैं, कैपिटलिस्ट्स हैं, सरमायेदार हैं । गरीब का काम वहीं रुका पड़ा है । आप गरीब के अलमबरदार हैं और ये लोग इस रास्ते में रुकावट हैं । इस रुकावट को लाजिमी तौर पर दूर करिये ।

इन अल्फाज के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे वक्त दिया । मिनिस्ट्री से मैं यह कहूंगा कि माइटिफिक तरीके से देश की हालत में सुधार लाने की कोशिश वह कर रहे हैं, इस तरह से वह लोग पकड़ में आ सकते हैं, जुर्म कम हो सकते हैं, तेजी से काम चल सकता है और वह सारी की सारी जो रुकावटें हैं उन को दूर किया जा सकता है, इसलिए साइंटिफिक लाइन पर सारी पुलिस को वह ले आयें और पुलिस को भी मकान की और दूसरी और सहूलियतें देनी चाहिएं । साथ ही सिपाही को ढंग से इस बात की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि उसको आज इस बीसवीं सदी में किसी के पास पहुंचने के लिए कितनी तहजीब, तमद्दुन, एहतियात और होशियारी से काम करना है । इन अल्फाज के साथ मैं आप का फिर शुक्रिया अदा करता हूं ।

13.27 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : श्रीमन्, विगत वर्ष गृह मंत्रालय की घोर असफलताओं का वर्ष माना जायेगा । चाहे आप असम की भाषाई अशांति और उपद्रव को ले लें या आप आन्ध्र प्रदेश की उस तहरीफ को ले लें जो मुल्की आईन और पृथक्करण को ले कर बड़े पैमाने पर हुई थी, किसी भी मामले में हम ने गृह मंत्रालय की दक्षता का

प्रमाण नहीं देखा । और मालूम होता है कि कुछ हाउजवाइफ की तरह सारे मसले को बिलकुल कारपेट के नीचे ढक देने में ही गृह मंत्रालय विश्वास रखता है । अभी तक असम के सम्बन्ध में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे मालूम हो कि भविष्य में उस तरह की अशांति फिर वहां नहीं खड़ी हो जायेगी ।

साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस माननीय गृह मंत्रालय की निष्पक्षता के सम्बन्ध में जितना गहरा सन्देह उत्पन्न हुआ उतना कभी नहीं हुआ था । आज तो सी०बी०आई० के बारे में ही यह सन्देह होने लगा है कि क्या इस को एक दल विशेष यानी सत्तारूढ़ दल के स्वार्थ साधन का माध्यम नहीं बनाया गया है ? दिल्ली की पुलिस का तो ऐसा हाल है कि हम मजबूर होते हैं यह कहने को कि वह सत्तारूढ़ दल के स्वयंसेवक दल की तरह काम कर रही है । इस सदन में कई बार जोर देकर बताया गया है कि विरोधी पक्ष के कार्यालयों पर पुलिस की मौजदगी में किस तरह से कुछ लोगों ने आक्रमण किये । उन घटनाओं का पूरा वर्णन करना इस सभा के सम्मुख अभी संभव नहीं है । अभी हाल में मिरांडा हाउस में जिस तरह की घटना हुई और पुलिस ने वहां कार्यवाही करने में जैसी हिचकिचाहट की उसका हम ने कुछ ही दिनों पहले यहां जिक्र किया था । आज तक जनता के दिमाग से यह संदेह दूर नहीं हुआ कि क्यों उस गाड़ी को नहीं पकड़ा गया जिस गाड़ी के नम्बर और रंग को वहां की लड़कियों ने बताया था । एक ही कारण उसका मालूम होता है कि वह जिस व्यक्ति की गाड़ी थी वह एक पूंजीपति है और वह सत्तारूढ़ दल की महासभा का सदस्य है, इसीलिए उसकी गाड़ी को नहीं पकड़ा गया । यह तो यहां की पुलिस का हाल है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी लड़कियों की जान और इज्जत के साथ इस तरह पुलिस खिलवाड़ कर सकती है तो आम जनता के जानोमाल का क्या हाल होगा---आप इसका सहज ही में अन्दाजा कर सकते हैं । अगर आप मोदी-काण्ड को ही ले लें तो इसमें भी पुलिस का जो हाल रहा या यहां के प्रशासन का जो हाल रहा है, आप उससे पूरी तरह से अवगत हैं श्री मोदी के ऊपर मेन्टेनेन्स आफ़ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट के अन्दर जो कार्यवाही करने की बात की गई थी, जो दफ़ायें लगाई गई थीं, उसको क्यों हटा लिया गया ? इस बात पर सभी दल एक मत हैं कि जमाखोरी के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए । अगर ऐसी बात है तो ऐसी जमाखोरी की जो मिसाल हमारे सामने आई और जो रंगे हाथों पकड़ा गया, उस पर क्यों "मीसा" के अन्दर कार्यवाही नहीं हुई---इसकी सफ़ाई भी सरकार आज तक नहीं दे पाई है । अगर यहां के गवर्नर साहब ने सख्त कार्यवाही करने का आदेश नहीं दिया और उसको उठा लेने की बात की, तो मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब ने उचित बात नहीं की और उनके ऊपर गृह मंत्रालय का दबाव पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया ।

अब मैं एक दूसरी बात को लेता हूं जिस के सम्बन्ध में यहां पर कई बार चर्चा हुई है तथा गृह मंत्रालय की निष्पक्षता के सम्बन्ध में सन्देह बढ़ा है । जिस तरह से हरियाणा के मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी ने, जो इस समय गृह मंत्री हैं, लेकिन उस समय स्वास्थ्य मंत्री होते थे, उन के पाक-साफ़ होने की घोषणा की थी जब कि उनके ऊपर जांच-पड़ताल चल रही थी । इससे सब को मालूम हुआ कि उनका कितना पक्षपातपूर्ण व्यवहार रहा है । हम ऐसे गृह मंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगले वर्षों में उनके मंत्रालय की जो कार्यविधि होगी, उसमें वह पूरी तरह से निष्पक्षता बरतेंगे ? मैं आप से साफ़ तौर से पूछना चाहता हूं---गृह मंत्री के जो प्रतिनिधि

[श्री श्याम नन्दन मिश्र]

यहां बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं—क्या आपने अभी तक इस का कोई जवाब दिया कि जब हरियाणा के मुख्य मन्त्री के खिलाफ़ जांच-पड़ताल हो रही थी तो उस समय के स्वास्थ्य मन्त्री ने क्यों उनके पाक-साफ़ होने की घोषणा की थी, क्या आज इस तरह से शासन चलाना चाहते हैं, क्या इस तरह से लोकतन्त्र चलाना चाहते हैं ? और, वही साहब आज गृह मन्त्री बन कर बैठे हैं। इसलिये यह बिल्कुल साफ़ है कि इनमें वह क्षमता नहीं है कि पूरी निष्पक्षता से गृह मन्त्रालय की कार्यविधि को चला सकें।

आप अल्पसंख्यकों की बातों को ही ले लीजिये—जिसके सम्बन्ध में यहां पर काफ़ी चर्चा हुई है। अल्पसंख्यकों के दिमाग़ में आज जितनी चिन्तायें हैं, यदि उनको दूर नहीं किया तो एक बड़ी विचित्र परिस्थिति यहां पैदा हो जायेगी। गृह मन्त्रालय इसके लिये साफ़ तौर पर जिम्मेदार है कि अल्पसंख्यकों के दिमाग़ में इस तरह की निराशा या चिन्तायें बढ़ी हैं। नेशनल इन्टीग्रेशन कौन्सिल जिसकी स्थापना बड़ जोर शोर से हुई थी—आज वह (नेशनल इन्टीग्रेशन कौन्सिल) कहां है ? हम रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि नेशनल इन्टीग्रेशन कौन्सिल के सचिवालय का विस्तार हो गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नेशनल इन्टीग्रेशन कौन्सिल की बैठक कितने दिनों से आज तक नहीं हुई। ऐसा लगता है कि नेशनल इन्टीग्रेशन कौन्सिल को किसी बरफ़ानी चादर की कब्र में रख दिया गया है—यह हालत है आपके नेशनल इन्टीग्रेशन कौन्सिल की।

दूसरा कारण जो अल्पसंख्यकों के दिमाग़ में चिन्ता का है, वह यह है कि जब हम मूलभूत अधिकारों के सम्बन्ध में यहां पर एक विधेयक पर चर्चा कर रहे थे तो विरोध पक्ष वालों ने कहा था कि आप अल्प संख्यकों के मूलभूत अधिकारों को न छूयें, उसको स्पर्श न करें, उनके अधिकार अक्षुण्ण रहने चाहियें, उनके फण्डामेन्टल अधिकार ज्यों के त्यों रहने चाहियें और उनमें संशोधन करने की इजाजत सदन को नहीं होनी चाहिये। उस समय हम लोगों ने फ्रेंक एन्टनी साहब के एक संशोधन पर मुत्तहदा तौर पर वोट दिया था, लेकिन सरकार ने हम लोगों की राय नहीं मानी। आज इससे भी अल्पसंख्यकों के दिमाग़ में बहुत कुछ चिन्ता पैदा हो गई है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जिस तरह से विधेयक लाया गया, मैं आपसे साफ़ तौर पर निवेदन करना चाहता हूं, उससे इस सदन का सिर शर्म से झुक जाना चाहिये जब हम उस पर विचार कर रहे थे, उस समय जिस तरह से उस विधेयक पर तरमीमों पर तरमीमें आ रही थीं, कागज के पुर्जे आ रहे थे, सदन में काम करने का यह ढंग नहीं हो सकता और हमने उस समय भी विरोध किया था और आज भी विरोध करते हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विधेयक को जिस तरह से यहां लाया गया, जिस तरह से पेश किया गया वह गलत तरीका था और उसी का नतीजा आज आप देखते हैं, आज उस कानून को लेकर कितना घोर असन्तोष चारों तरफ फैला हुआ है। वह बिल्कुल अलोकतान्त्रिक विधेयक यहां पर लाया गया और उसी तरह से वह पास भी हुआ।

तीसरा कारण जो अल्पसंख्यकों के दिमाग़ों में चिन्ता पैदा करने का है—मैंने अभी उस रिपोर्ट को पूरा नहीं देखा है, फ्रेंक एन्टनी साहब मौजूद हैं शायद उनको याद होते—कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस करते हुए एटार्नी जनरल ने कहा था—दि राइट आफ रिलीजन इज़ नाट ए फण्डामेन्टल राइट। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप के एटार्नी जनरल को ऐसा कहना चाहिये ? मैं ज़रा इसके बारे में चैक करूंगा, मेरे पास फाइल है, अभी मैं उसको पूरी तरह से देख नहीं पाया हूं, लेकिन जहां तक मुझे याद है, उसी के आधार

पर कह रहा हूं और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो माननीय मन्त्री जी उसका संशोधन कर दें, मैं उनकी बात मान लूंगा । जिस राज्य का एटार्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर कहे--दि राइट आफ़ रिलीजन इज़ नाट ए फण्डामेन्टल राइट, तो आप समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के दिमाग पर उसका क्या असर पड़ेगा । मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें ।

मेरा साफ सुझाव है--अगर आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यक यहां पर अच्छी तरह से रहें और उनके दिमाग पर किसी तरह की चिन्ता या अन्देशा न हो तो आप को एक विजिलेंस कमीशन की तरह से "सिविल राइट्स कमीशन' बनाना चाहिये । उस सिविल राइट्स कमीशन को यह अख्तियार हो कि अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर विचार करे और उन पर अपना निर्णय दे । बहुत सी शिकायतें इस तरह की होती हैं कि उनके ऊपर कानूनी तौर पर फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन यह कमीशन उसमें जा सकता है और उस के बारे में फैसला कर सकता है । इसीलिये सुप्रीम कोर्ट के एक भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश ने इसी तरह का सुझाव दिया था । और मैं यह भी समझता हूं कि अल्पसंख्यकों के जो हुकूक होने चाहिये, आर्थिक जीवन में या रोजगारी में, उन को भी देखना होगा, वरना उन के अन्दर एक बड़ी गहरी अशांति पैदा हो जायगी । हम कहते हैं कि बहुत से नौजवान आज बिलकुल निराश हो रहे हैं, बौखला रहे हैं--निराशा और बौखलाहट बहुसंख्यकों में भी हो सकती है, लेकिन अल्प संख्यकों में ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में मेरा ख्याल है कि जहां उन को मिनिस्टर बनाना आसान है, उन का खानसामा बनना मुश्किल है । मैंने पहले भी एक बार इस सदन में कहा था और आज उस को फिर दोहराना चाहता हूं--एक मसलमान के लिये मिनिस्टर बनना आसान है, खानसामा बनना मुश्किल है । आप मिनिस्टर बना देते हैं--नुमाइश के लिये, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिये, लेकिन जहां तक मुसलमान नौजवानों के लिये रोजगार का सवाल है, वह खानसामा भी नहीं बन पाता । इसलिये मेरी यह राय है कि इकानामिक-लाइफ, राष्ट्रीय आर्थिक जीवन में उनको न्यायपूर्ण और उचित स्थान मिलता है या नहीं, इस के लिये एक कमीशन बनना चाहिये । हम कई बार देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से, व्यापार या उद्योग के क्षेत्र में उनका जितना स्थान होना चाहिये, उतना नहीं मिल पाता है ।

अब मैं एक शब्द मद्य निषेध के बारे में कहना चाहता हूं--मद्य निषेध योजना को सरकार ने जिस तरह से खत्म कर दिया है, यह बड़ी निन्दा की बात है । मेरा ख्याल है कि सरकार ने जो हमारे निदेशक सिद्धान्त हैं उन की अवहेलना की है, वरना क्या आज आप ऐसी बातें देखते कि महाराष्ट्र में शराब की कीमतों में 30 फीसदी की कमी की जाय और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें 30-35 प्रतिशत बढ़ जायें यह तरीका है हमारी सरकार का और विशेष कर सत्ता रूढ़ दल का इस देश में मौरल-क्लाइमेट बनाने का । अगर यही तरीका देश में वातावरण बनाने का चलता रहा तो मैं समझता हूं कि इस देश में वैसे हिप्पी पैदा होंगे । जिनके ज्यादा खतरनाक होने की बात आप समझ सकते हैं । दूसरे देशों में जो हिप्पी बनते हैं वे वहां ऐफ्लुएन्स के आधार पर, समृद्धि के आधार पर बनते हैं । लेकिन हमारे यहां जो हिप्पी बनेंगे वह बेकारी और गरीबी के आधार पर बनेंगे और वे बड़े खतरनाक होंगे ।

आखिरी बात यह है कि फीडम फाइटर्स, स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन देने की जो बात कही गई है उसमें जिस तरह की रुकावटें आ रही हैं और जिस तरह से लोगों को तरदुद का सामना करना पड़ रहा है वह इस शासन के लिए और इस सदन के लिए शोभनीय नहीं है । यह सारा सदन उस तहरीक की

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

औलाद है जो स्वतंत्रता सेनानियों ने यहां पर पैदा की थी । आज उनको तरह-तरह की ठोकरें खानी पड़ती हैं और उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे है । इसके लिए मेरा एक सुझाव है । अगर आप 6 महीने या साल भर के सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो आप बहुत सी जगहों में देखेंगे कि पन्ने के पन्ने गायब हैं किताबों से तो फिर वे लोग करें क्या ? इसलिए ऐसा होना चाहिए कि हर एक जिले में एक सर्वदलीय समिति जाये और दो तीन दिनों में फैसला कर दे कि कौन से व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 6 महीने या उससे ज्यादा जेल की सजा भुगती थी । इस तरह से यह मामला बिल्कुल साफ हो जायेगा और उसमें किसी तरह का कोई तरद्दद नहीं उठाना पड़ेगा ।

इसके साथ-साथ जो हमारे क्रान्तिकारी साथी थे उनके साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है । जेल में उन्होंने सजा भुगती थी लेकिन उनके ऊपर खून की या दूसरी दफायें लगाई गई थीं । आज उनको मान्यता नहीं दी जा रही है । उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है, मेरे पास खत आया था, कि अगर सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया तो वे मजबूर होंगे उन रास्तों को अख्तियार करने के लिए जो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अख्तियार किए थे । इस लिए मैं चेतावनी दे देना चाहता हूं कि उनके लिए भी कायदे काफी सहज बनाये जायें ताकि उनको भी मदद मिलने में आसानी हो ।

SHRIMATI JYOTSNA CHANDA (Cachar): Mr. Deputy-Speaker, I find from the report of the Ministry of Home Affairs that there has been mention of violence and tension in Assam in 1972. I am sorry to find that no mention has been made about the loss of property of lives; I would have been glad if. I could find it, While rising to support the demands, I should like to draw the attention of the Government to the disturbances in Brahmaputra valley in the later part of 1972 in the name of language. Language distrbances have become a constant feature in Assam and have occurred in various occasions, the most serious one being those in 1972, that is, after the census. Each time the State machinery failed to meet the situation and this time the conduct of the police was reprehensible. It is unfortuate that the Union Government's belated action gave indulgence to parochial, linguist chauvinists and hooligans. Those officers who had been responsible for dereliction of their duties have not yet been found out or taken to task. The employees of the All India Radio stations of Gauhati and Dibrugarh who indulged in anti-Bengali propanganda had been merrily spreading the venom through drama and other things and it is sad that the Union Government had not taken any action about those radio stations. Unless exemplary punishment is given to those who either helped or abetted the hooligans, the danger of recurrence is always there and it is this parochialism and linguistic chauvinism released by a section of the Assamese leadership which has resulted in the bifurcation of the State of Assam into Nagaland, Arunachal, Meghalaya and Mizoram. They have all gone out of Assam.

The result of imposition of Assamese language is the main cause of it. There is again a demand from the people of border areas of North Cachar Hills.

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar): represent Cachar.

SHRIMATI JYOTSNA CHANDA: He represent everybody in this country. As I said, a section of the people in Cachar demand for separation from the State of Assam. I would like to cite in this connection a poem which I learnt in my child-

hood. When a person, named Shri Haradhan who had 10 sons sent his sons to a jungle, they all roamed about. But, one was lost in the jungle. Then nine of them went. One of them was lost when they went to cut wood in the jungle. One of them died of snake bite. In this way when nine sons were killed, the tenth boy was frustrated. He too went to the jungle and lost himself. The same thing will happen to our State—Assam. I am afraid of it. Along with the language issue, has cropped up their grievances in regard to employment facilities for lack of industrial developments of their areas.

Coming from Cachar, I can mention that the treatment to non-Assamese areas is stepmotherly. For instance, both the Silchar and Gauhati Medical Colleges were to be started simultaneously. The Gauhati Medical College is now a full-fledged one and the Silchar one is struggling for existence. Proper provision has not been made as yet to satisfy the Indian Medical Council for giving proper recognition. Similarly is regarding the provision for the Regional engineering College in Cachar, the fate is that the principal and the staff are enjoying in Shillong while there is very little sign of the Engineering College to come into existence.

In the field of development, Cachar is most neglected so far two industrial projects have been sanctioned-one a sugar mill and the other a paper mill, but the progress in those two is so slow that one never knows how long it will take to commission both the projects.

Fruits are grown in abundance in Cachar, but the fruit preservation factory is not capable of handling huge quantity—the State Government does not take proper care and the agriculturists suffer economically.

Unemployment question is a serious problem in Cachar but unfortunate part is that the boys of the linguistic minorities do not get equal opportunities. The ethnic minorities in Assam are deprived of getting their due share in recruitment to State services, State undertakings. The Bengali speaking candidates are discriminated. The employment Exchanges in the State of Assam acting under secret directives from the State Government, refuse registration to Bengali-speaking job seekers in Brahmaputra Valley and they do not generally forward the Bengali names to Banks, State undertakings, Railways, Private Sector Companies etc. The names of the job seekers from Cachar also meet with the same fate. The cases of other ethnic minorities are no better, they have not yet received their full share in State Government employment and their representation in Public Sector Undertakings, Nationalised Banks etc. is almost negligible. This situation calls for immediate remedial measures.

Now, coming to the question of fundamental rights of the linguistic minorities, I can cite an example where Assam Government do not care even to honour the constitution provision in respect of primary education. The Constitution provides that "the medium of instruction at the primary stage should be the mother tongue of the child provided the stipulated strength of pupils is available." But the Assam Government, in violation of this, has laid down that "the language/dialect to be accepted as the mother tongue for the above purpose will be in accordance with a list prepared from time to time and approved by the State Government". This is from the Twelfth Report of the Linguistic Minorities Commission. The Assam Government have thus reserved to themselves the right to recognise or not any mother tongue as the medium of instruction at the primary stage, even if the stipulated number of pupils is forthcoming.

This provision has actuated the Assam Government to start a few

[Shrimati Jyotsna Chanda]

primary schools in Assamese in Hailakandi of Cachar district by spending good amounts and depriving the Bengali medium primary schools. Similarly efforts were made last month in Fulertal in Cachar where the General Secretary of All Assam Students Union, along with some office-bearers of Asom Sahitya Sabha were sent from Kumbhirgram aeredrome under police escort to further Assamisation there, with the help of some agents favoured by the State Government and Asom Sahitya Sabha.

Similarly in the case of secondary education, though the directive of the Union Government is for non-diminution of facilities in mother tongue in secondary level, the attitude of the Assam Government is quite contrary.

There is no protection for linguistic minorities. Their constitutional rights are denied, Employment facilities are not there. For all practical purposes, the linguistic minorities are all second class citizens in the State of Assam. Assam Panchayat Bill, 1972 has deprived representation to tea garden labourers who are of non-Assamese origin.

I would request the Union Government either to implement the rights of the minorities and find ways and means for the protection of those rights or separate the territories which are non-Assamese speaking, into different units and bring all the units under the Eastern Zonal Council. Fragmentation of North Eastern Region is necessary for national integration and this may strengthen the ties between Assamese and non-Assamese. Otherwise, the inherent bitterness of one about the other will weaken this vulnerable frontier zone.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Dharapuram): Sir, I regret to say that the report of the Home Ministry is a mere repetition and there is nothing new to welcome in it. Yesterday there was some interesting debate. One Mr. Gopal from the Congress side spoke and we saw for the first time a strange and grand alliance between the ADMK member and the Congress member from Tamil Nadu. —Mr. Manoharan and Mr. Gopal openly coming out with their solidarity. Mr. Gopal has used words like mass upsurge, revolt, reign of terror of the DMK Government prevailing in Tamil Nadu according to him. I do not know what he means by it. In my humble opinion, by using strong words he is establishing the fact that he is now in politics.

Another member, Shri Manoharan, has spoken almost in the same vein. The team work which they exhibited yesterday will confirm the feeling that we can call them as a Grafted Congress. There are two Congresses in the country, namely, Congress(R) and Congress (O). In Tamil Nadu there are three Congresses, namely, Congress (O), Indira Congress and Grafted Congress of which Shri Manoharan is a member.

Shri Manoharan in his speech said many things about the DMK Ministry in Tamil Nadu and its members. He started speaking about corruption and nepotism and tried to boost up his popularity. The whole world knows the type of people in his party. Corruption, cheating, immorality, holding black money etc. deserve the heaviest punishment and condemnation from all. Whether in politics, big business or film industry, such people should be punished.

What can we say about a person who stoops to the level of claiming a sum of Rs. 1,000 when a party of members visited the Aligarh Muslim University some time back, at the same time cheating the party by claiming allowance from Parliament also? When somebody in the party questions the propriety of this, he goes out and accuses others of corruption. A man who came to politics with nothing in hand is now worth several lakhs. It is nothing but ill-gotten wealth and he owes an explanation to the people

of Tamil Nadu how he got these riches. Instead of objecting himself to an inquiry, he is asking for an inquiry about others.

Tamil Nadu is the only State which has laid down a rule, after the DMK coming to power that every member in the Council and Assembly, including the Ministers, should declare their assets and liabilities every year. Every Minister and every member has complied with this rule and those records are available for public scrutiny. Only one MLA in the Tamil Nadu Assembly has refused to declare his assets and liabilities, in spite of 13 reminders from the Assembly Secretariat. Who is that MLA of Tamil Nadu who did not care to reply to 13 reminders? He is the leader of Shri Manoharan now, Shri M. G. Ramachandaran.

There was a DMK conference in Madurai last year in which Shri Manoharan and his present leader participated. The latter spoke very vehemently and said he was prepared to face the army sent by Shrimati Indira Gandhi. Probably the Home Ministry knows what happened to that leader. Instead of sending an army of soldiers, an army of income-tax officers and enforcement directorate officials invaded him. The income-tax department, which is nothing but a political tax department, reopened his past accounts and claimed that he should pay income-tax to the tune of Rs. 29 lakhs. Moreover, the Enforcement Directorate was asked to send a directive under section 19(2) of the Foreign Exchange Regulation Act. It is alleged that when he went abroad for shooting films, he violated some of the provisions of the Foreign Exchange Regulations Act. We asked a question in this House in the last session about the details of the directive and the reply given by him. The Government admitted proceedings under that Act but did not disclose the details in public interest. In whose interest? Everybody knows that it is in the interest of Shri M. G. Ramachandran. I do not know whether this case will ever see the light of day. I think it is enough evidence to prove that he has violated the Act. The man who said with bravado that he will face the army, now, after this case, has tumbled in his shoes and prostrated himself before the Congress Government. This conspiracy is fully exposed and the people of Tamil Nadu are keenly watching what would happen to his income-tax arrears and foreign exchange violations. So, this phenomenon of A.D.M.K. is nothing but creation of interested parties in Delhi.

14.00 hrs.

Coming to the Centre-State relationship, this is what the then prominent Member of this House had said:

> "The two charity boys belonging to the Central Cabinet—one is Mr. C. Subramaniam and the other is Mr. Mohan Kumaramangalam—these people came to Madras and addressed the people of Tamil Nadu at a meeting....."

This was spoken by Mr. K. Manoharan, the then prominent Member of this House last year in the very same House here. They have now become charitable masters and he is echoing His Master's Voice.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): Master's voice or Mistress's voice!

SHRI C. T. DHANDAPANI: Not only that. Yesterday, he said something about our Ministers also. He gave a very good chit to Mr. Sanjay Gandhi. We have no objection to that. But it seems Maruti Car made an advertisement for wanting an announcer—Mike boy. I think, Mr. Manoharan will well fit in that job. When he made a mention of an Aryan Chief Minister, he said thousand Aryan Chief Ministers equal to one Mr. Karunanidhi. Actually, Mr. Karunanidhi's efficiency and capacity is equal to thousand Congress Chief Ministers.

[Shri C. T. Dhandapani]

The most important point that I want to make is about Hindi. Last time also, I touched upon this matter. In UPSC examinations, the candidates are allowed ony to right their examinations in Hindi or English. Mr. Mirdha must be knowing it. Whereas, our people coming from non-Hindi area will suffer very much. As the Minister promised in the very same House, all the regional languages mentioned in the Eighth Schedule should be taken as a medium of examination.

At the same time, in the 12th Report of the Commission on Linguistic Minorities of India, on p. 4, it is stated:

> "The knowledge of the State official language should not be a pre-requisite for recruitment to State services and option of using English or Hindi as a medium of examination should be allowed. A test of proficiency in the State official language should be held during the period of probation."

This is what is stated in the Report. For non-Hindi area people, it has been stated that they can appear in their own language only after they have got appointment. But all the same, for the people coming from Hindi area, that is not required.

Another important point that I want to make is this. The D.M.K. party protested against it last time and for some time, we were not participating in the question Hour also, that is, about the use of Devanagri script for Hindi and English. The Report says:

> "With a view of allaying the apprehensions of the Central Government employees in regard to the form of Hindi language to be used in the official work, instructions have been issued that they can use mixed language and are free to use English terms in Devanagri script."

That way, for example, for the word "betray", the equivalent to Hindi is "Dagabaz" and they can very well use English letters for that.

In that case, people from non-Hindi Hindi speaking areas will certainly be penalised much. For development of Hindi, Government spent about Rs. 25.45 crores in the Fourth Five-Year Plan, whereas only Rs. 1.35 crores were allotted for the development of other languages. In the Fifth Five-Year Plan, Rs. 21 crores have been sanctioned for development of Hindi. You go on helping the Hindi States, helping the students coming from Hindi-speaking areas, but our students from non-Hindi speaking areas are deprived of these things. I want to give an example. From 1966 to 1972, 707 IAS officers were selected. Out of that, five Hindi-speaking States, including Delhi, got 346 posts. In the same manner, in the case of IPS, 444 candidates were selected out of which these States got 243. Actually students coming coming from non-Hindi speaking areas are deprived of these things. Therefore, I request that the regional language also should be introduced.

My hon. friends and others have said about the Commission of Inquiry and other Acts. We, in our State, have brought out a comprehensive Bill to enable a person to prefer a complaint alleging corruption about a public man and to provide the necessary agency to conduct the investigation and inquiry into the allegations. This Bill seeks to achieve removal of corruption and other things. Two State Governments, Rajasthan and Maharashtra, have passed legislations on the same lines. The Tamil Nadu Government have recently introduced a Bill specifically to inquire into the allegations of corruption against the Ministers, including the Chief Minister. The Commission will have a judge equivalent to a High Court judge who will be appointed on the recommendations of the Chief Justice of the

High Court. This clearly shows that he will be an independent man to inquire into the allegations. His term will be three years. Unlike the 1952 Central Act, anybody can approach the Commission demanding an inquiry against Ministers, State Legislators and Chiefs of local Boards. No sanction from the State Government for making an inquiry is necessary. If the Commission gives the findings that the allegation of corruption is proved, then the Government has no option except to prosecute the Minister. The term of punishment is seven years. There is no such provision in the 1952 Central Act. Even in the legislations passed by Maharashtra and Rajasthan, there is no provision to include the Chief Minister of the respective State under the purview of the Act. Under the Tamil Nadu Bill, if the Commission finds a Minister guilty, the State Government shall take proceedings in a court of law for such corruptions under the Criminal Law Amendment Act. So, there will be a regular criminal case against him for which appeal is provided.

Before I conclude, I want to make one point. The DMK government has been elected by the majority of people. We are introducing progressive measures in our State. I do not know why the Congress Government at the Centre—some of their Ministers and leaders—are unnecessarily interfering in the administration of the State Government. I want to ask them whether the DMK Government is lagging behind in the implementation of progressive programmes in our State. I make this challenge. Any Member can come to Madras and see the development of our State. Instead of doing that, this Government is actually creating and encouraging defections, thus creating an unhealthy practice, unhealthy situation, in politics. Certainly, they have purchased some members from this side. We know. But at the same time, Mr. Manoharan and others have some hold in the Congress but not among the masses.

Before I conclude, I want to recite a poem:

"Thou slave, thou wretch, thou coward,
Thou little valiant, great in villainy,
Thou ever strong upon the stronger side,

Thou Fortune's champion, that dost never fight
But when her humourous ladyship is by
To teach the safety."

By saying this, I conclude my speech.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): I want to raise a small point of order regarding the report that has been presented by the Home Ministry.

You are fully aware that in the year 1970 when there was a move to introduce the Hindi names in Roman *lipi*, there was a very huge objection from this side of the House and it was agreed on the floor of the House and the Minister of Parliamentary Affairs then said that the present English name will be retained and the Hindi equivalent in Devnagari script will be inserted in all the communications. That was agreed to in the House. But if you take the report printed this year, it says:

"Government of India
(Bharat Sarkar)
Ministry of Home Affairs
(Grih Mantralaya)"

This goes against the assurance given to the House. If they want they can put these things in the Devnagari lipi. Sir, this is the thin end of the wedge.... (*Interruptions*). It goes against the assurance given to this House.

MR. DEPUTY SPEAKER: It is no point of order. You should have raised it in the very beginning. Now, we are at the end of the debate and when the Minister replies, he can

[Mr. Deputy-Speaker]

reply to it. But, in my view, there is no point of order.

Now, in view of the long list of speakers from the Congress side, they will not be given more than seven minutes each.

SHRI PAOKAI HAOKIP (Outer Manipur): I am glad you have given me an opportunity to speak on the Demands for Grants of the Home Ministry.

In the first place, I welcome the new Minister, Mr. Uma Shankar Dikshit to take up this important portfolio and take keen interest in the welfare and upliftment of the down-trodden people mainly, the tribals.

I know I have a very limited time but I have so many things to submit before this august House. So, I will try to be as brief as possible.

For the last 25 years since the attainment of independence, the conditions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have not improved and they are in the same conditions as they were before the attainment of independence. It is very sad for this House, not for me alone, not for any Scheduled Caste or Scheduled Tribe individual, but it is very sad to every Indian that during the 25 years of freedom there has been no worthwhile progress achieved by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. No doubt, some progress on the educational front and in the economic front is there but I wanted to submit to you that the Schedule Castes and other Backward Classes have not been able to achieve much during the last 25 years. That is my point. This happens because of what? Because, the hon. Members opposite always come to the august House and say that nothing has been done for the backward people, for the scheduled caste and scheduled tribe people, by the Government. I would, with all respect, appeal to hon. Members on that side that, instead of charging the Government, if they are really interested in the welfare of scheduled caste/scheduled tribe and backward people, whenever a situation or incident or accident takes place in any part of the country, they should not try to politicalise the situation but they should see that the situation is taken in hand and controlled. Together with the ruling party every section of the Indian people should come out against such incidents. Merely coming to the House and charging the Government, saying Government is lacking in action and all that will not solve the problem. Therefore, I do not agree with the Members of the Opposition in their contention.

The House knows that the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people and Harijans especially have been the victims of Indian society for long. Every day we see in every part of the country some incidents of death taking place or atrocities committed in respect of scheduled caste and scheduled tribe people. I have no doubt that Government has been doing its level best. But it is not the responsibility of the Government alone. Government alone cannot tackle this problem. Our country is a vast country and our population is a vast population. It is therefore impossible for the Government alone to tackle this problem effectively. It is the direct responsibility of the nation, as a whole, to see that such situations do not take place. There should be collective responsibility for this.

AN HON. MEMBER: When a Member speaks about scheduled castes and scheduled tribes he may be given three minutes more..

MR. DEPUTY SPEAKER: I thought you would say something about Manipur.

SHRI PAOKAI HAOKIP: I am coming to that.

MR. DEPUTY SPEAKER: Your time is up. You have half a minute only. You may please conclude now.

SHRI PAOKAI HAOKIP: The conditions of the scheduled castes and scheduled tribes should be improved as quickly as possible. During the time of Bangla Desh atrocities 10 million refugees came to our country and they were adequately looked after. They were provided both food and clothing. But the down-trodden people here after 25 years of Independence are still in the same condition.

Now, coming to my State of Manipur the scheduled castes and scheduled tribes there have not been taken care of very much. The Home Ministry should see that their condition is improved as early as possible.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I will like to utilise this debate to focus the attention of the House sharply on two specific issues which are concerned with the Home Ministry.

Unfortunately, last year has been the year when the orthodxy in this country with its high priests have taken an offensive against the down-trodden section of our society and particularly harijans and adivasis. I do not want to mention just the list of atrocities that have been committed against weaker sections like Harijans and Adivasis but I would like to directly refer to the high priest of orthodoxy, that is, Shankracharya of Puri. I want to bring to the notice of the Home Minister that in the last few days Shankracharya of Puri has been conducting a campaign in my State and in meeting after meeting he has been making the most vulgar attack on the down-trodden sections and trying to preserve, violating all provisions of the Constitution, the existing caste system and the system of untouchability. If you just go through the record of his speeches you will find that in some of his speeches he has tried to justify social inequality. He has tried to philosophise the problem and he has tried to pose that if in nature inequality exists, in social field inequality is bound to exist.

I would like to point out to you that Shankracharya has gone to the extent of saying that if cats and dogs are not treated with an element of equality why should human beings be treated with an element of equality. He said it not merely in a speech but in an interview given to a Marathi paper of Bombay 'Navakal'. He has been making speeches and provoking Harijans. In a number of meetings addressed by Shankracharya progressive elements among the youth are staging demonstration and as a result of this confrontation a state of tension exists in different parts. But this Shankracharya of Puri goes scot free. More than the rape of Harijans and more than the molestation of the Harijans the defence of the rape by system, the defence of this vulgar system based on caste and community is the worst type of crime that can be committed. I demand that the Home Ministry should move in the matter and bring this high priest of orthodoxy, Shankracharya of Puri, who is actually guilty of this heinous crime, to book so that those who are suffering under the hegemony of such Sankaracharya will be liberated.

Fortunately, there is a new upsurge among the people. I am glad that even leaders like Shri Atal Bihari Vajpayee—you may not like it—are taking postures which are in the right direction. I am glad when he came to Bombay, he condemned this untouchability. Of course, he will have to go a long way and he will have to discard also the philosophical and ideological background that is given for the superstructure of the caste system that exists over here.

[Prof. Madhu Dandavate]

These are the leaders who are creating tensions in the society. They are justifying the existence of the caste system. As a result of that, everywhere peace is being destroyed. When these things happen, on some technical legal ground these young men who demonstrate against the Sankaracharya are arrested and put before the court. But you are not moving in the matter of action against the Sankaracharya who is violating the provisions of the Constitution. I demand that this should be done.

Fortunately, though you are not doing anything on the legal plane, on the popular plane those who are suffering under the tyranny of the Sankaracharya are telling the Sankaracharya: 'It might be in your interest to be our master, but how is it in our interest to be your slaves?' That new upsurge has dawned. I am sure that ultimately that will be the only factor that will determine whether this tyranny is to be continued or whether it is to be fought.

After this, I will come to a new tension that is being created on the question of the National Anthem. I am one of those who feel that the political parties in the country must take a firm stand and should not worry whether because of that particular secular and firm stand, they will lose votes or gain votes. Loyalty to the nation, the tradition of the country, loyalty to the memory of the freedom fighters is more important than a few votes that will be ascertained or secured.

In my own city of Bombay, a controversy about Vande Mataram was carried on by two extreme types of communalism. Those who never remembered Vande Mataram, when people were singing Vande Mataram and going to the gallows, when they were singing Vande Mataram and facing bullets and lathi charge, at that time some of these elements were nowhere to be seen near Vande Mataram at all. But they have become protagonists of Vande Mataram. On the other hand, as has been rightly quoted, it is elements inside the Congress Party, the leader of the Congress Party in the Bombay Municipal Corporation—it was not the leader of the Muslim League Party—who later raised a controversy about Vande Mataram. Strangely enough and unfortunately, he brought Allah into the picture. Thank God the Muslim League in this House is not bringing Allah into the picture. He said, 'we Muslims only bow before Allah and we bow before none else'.

In this very House, I am glad that every member, whether Hindu or Muslim, when he enters and leaves bows before the Chair. There is nothing wrong in that because this is the dignity and decorum to be observed. There are Muslims who have gone to the gallows with the slogan of Vande Mataram on their lips. This is the tradition of Vande Mataram.

I do not repeat what he has said and quoted. I will only quote a significant sentence of what the President of the Constituent Assembly declared when he was authorised to make a statement on the National Anthem. This is the significant part of it:

> "Jana Gana Mana is the national anthem of India....and the song Vande Mataram which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equal with Jana Gana Mana and shall have equal status with it.".

Then there was great applause.

MR. DEPUTY SPEAKER: He should conclude.

PROF. MADHU DANDAVATE: Give me only a few minutes more. I had written to the Speaker. I had tabled a call attention notice and short notice question. He said I could take time during the debate on the Home Ministry Demands and raise the issue.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may have written to the Speaker. As far as I am concerned, there is zero against your party so far as the time for this discussion is concerned.

PROF. MADHU DANDAVATE: I have been given a letter in writing and I have been told that I have been given 10 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have given you seven minutes.

PROF. MADHU DANDAVATE: 10 minutes. Shall I produce the letter? I have been given a letter in writing that "you are allowed 10 minutes." On which Demand I should speak? (*Interruptions*) The letter from the office is there; the cyclostyled thing.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. I will give you that time. Now, please sit down first. As far as I know, this is for the entire debate on all the Demands for Grants. You can take your 10 minutes now, but not even a second will be given to you on any other Demand for Grants.

PROF. MADHU DANDAVATE: I will not speak on any other Demand throughout this session.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. Three minutes more.

PROF. MADHU DANDAVATE: The issues I am referring to are so important that I do not wish to speak on any other Demand in this session.

Coming to this particular point, I said that this was the consensus that was evolved, and the President has declared that this is the policy of the country as far as the National Anthem and Vande Mataram are concerned.

I would not like to rub any community in the country and create any misapprehension. Therefore, I would suggest that men in public life belonging to various schools of thought and communities can sit together and see, whatever thing has been agreed to in the Constituent Assembly, how best it can be implemented. It will be a sad day for us when even on the issue of the National Anthem the country is going to be divided between Hindus and Muslims. I have confidence that if the Muslims are approached with the correct perspective and correct spirit, even the Muslims in this country will be made to respect Vande Mataram and I have every confidence. Therefore, I do not want to rub any community the wrong way.

In two minutes, that are left to me, I would like to refer to another point of interest. Unfortunately, one of the factors that have contributed to atmosphere of disintegration is the pending State border disputes. I would like to take this attitude, that it does not matter whatever decision you arrive at. But let there be a firm decision on the border disputes not guided by political expediency but guided by uniform, rational norms. There has been the Mysore-Maharashtra border dispute. Even if the decision goes against Maharashtra, I would not mind it, but I do not like the dispute to be kept pending. Evolve a uniform principle without fear or favour and apply it and try to settle it.

Every election, in the city of Belgaum which is in Mysore at present, has been won by the Maharashtra Ekikaran Samiti (Belgaum), and even after taking a democratic verdict in all the panchayat elections, in all Assembly elections and in all the local self-government elections actually no decision is being taken and, therefore, that is my only grouse. Let a decision be taken.

I would like to take this opportunity of bringing before the House a very important event. One of the members of the Maharashtra Legislative Council, Mr. Datta Tamhane, has declared that "I do not want violence to take place in the Maharashtra-Mysore dispute. Since I do not want to attack anyone else, I am prepared to die myself," and therefore he has declared on the floor of the Maharashtra Legislative Council that "I am prepared, as a Gandhian, to resort to the

[Prof. Madhu Dandavate]

path of self-immolation, to rouse the conscience of the Lok Sabha and to rouse the conscience of the Government." I feel that we should not force the sincere, sensitive individuals and youth to be driven to that particular path. On the basis of a uniform policy, this should be done. Therefore, in this very context, I would like to say that the problem of Andhra, and of other parts, the dispute must be settled in time guided by the democratic wishes of the people. If you want to bifurcate the State, I have not the least doubt that ultimately Andhra Pradesh is going to be bifurcated—do it in good time and do it with grace. That is all I wanted to say.

I have taken more time. These are the issues on which I sought the permission of the Speaker to speak and took time. I was under the impression that 10 minutes were given to me and that is why I spoke. I will not speak on any other Demand in this session.

श्री टी० सोहनलाल (करोलबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन में बोल रहा हूं। सरकार ने जितने भी कार्य किये उन कार्यों को विफल करने के लिए इस मुल्क के अन्दर ऐसी ताकतें आज भी मौजूद हैं जो यह दिखाना चाहती हैं कि यह सरकार बिल्कुल निकम्मी है। यह बात आज से नहीं चल रही है—जैसा कि अभी मेरे एक मित्र ने बताया — अगर हिन्दू समाज में यह बात न होती तो पाकिस्तान नहीं बनता, बम्बई में जो कुछ हो रहा है, वह न होता। मगर उससे भी आज तक हिन्दू समाज ने सबक नहीं लिया, अभी भी उसको होश नहीं आ रहा है। शंकराचार्य की घटना अभी हो कर चुकी है—आज से ही नहीं, पांच-दस सालों से ये बातें हो रही हैं, मगर गृह मन्त्रालय पता नहीं कहां सो रहा है, ऐसे आदमियों को क्यों बन्द नहीं करता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितनी पार्टियां हैं, अगर वे इस मामले में एक हैं तो उन्हें मिलकर इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। इस शोषित समाज के लिए शंकराचार्य ने पिछले 10 सालों से जो जहर उगलना शुरू किया है उसको फौरन कन्डेम किया जाय, उसकी बुराई की जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, सबको मतभेद भुलाकर एक स्वर में आगे बढ़ना चाहिए—वरना 9-10 करोड़ का यह तबका —वह फिगर है जो गवर्नमेंट ने दी है, वरना उनकी तादाद 15 करोड़ है—किसी दिन वह वावेला मचा देगा कि वही कहावत होगी कि दूसरों को भी जो अपने आपको अच्छा समझते हैं उनको भी अपनी तरह से खराब करके छोड़ेगा। यहां पर जब दीगर पार्टियों के लोग बातें करते हैं तो वही कहावत सामने आ जाती है—जैसे कोई आदमी मर जाय, तो उसको उठाकर राम-नाम-सत्य है, कह कर ले जाते हैं और ईश्वर के नाम पर पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन जब फूक कर घर आते हैं तो सब भूल जाते हैं और उसी धन्धे में लग जाते हैं—वही चीज यहां पर होती है। जब हाउस के अन्दर बोलते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मगर जब बाहर प्लेटफार्म पर बोलेंगे तो सब भूल जायेंगे, वहां पर इस बात के लिए कोई कन्डेम नहीं करेगा। इसलिए मैं अपील करूंगा कि जो बातें मुल्क के लिए हानिकारक हैं, उनको कन्डेम किया जाय।

अफसरशाही का भी यही हाल है। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित-जन-जातियों के मामले में अगर किसी डिपार्टमेंट को कोई पत्र लिखा जाता है तो उस व्यक्ति से कहा जाता है कि तुम वहां गये थे, जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा। मेरे पास मिसालें हैं। दो-दो, तीन-तीन साल से जो लोग टम्परेरी काम कर रहे थे, उनके बारे में लिखा गया कि इनको परमानेन्ट किया जाय, रेगुलर किया जाय तो उन टम्प्रेरी लोगों को भी भगा दिया गया, बल्कि इस तरह से टांट कसा जाता है —लो, जगजीवन राम जी

आ गए हैं—यानि जो भी शेडयूल्ड कास्ट या शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लोग जाते हैं, उनको कहते हैं कि जगजीवन राम जी आ गये हैं, इनकी सेवा करो। क्या गृह मन्त्रालय इन बातों को देखेगा? अगर सही मायनों में गृह मन्त्रालय इन चीजों को देख ले, जिनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिले तो हम लोगों को देखना न पड़े।

अभी मैंने देखा कि एक आदमी ने बहुत अच्छा काम किया। उस आदमी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने वफादारी और ईमानदारी का परिचय दिया था। लेकिन जब उसको प्रोत्साहन देने के लिए लिखा गया तो अफसर यह कहने लगे कि यह तो इसकी डयूटी है : एक आदमी जो पैसा कमाता है, बेइमानी करके, उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन दूसरा आदमी जो अच्छा काम करता है, जिसके लिए लिखा जाता है कि उसको प्रोत्साहन दिया जाय, उसकी वाकायदा इन्क्वायरी होती है और सब बातें सही साबित होती हैं, उसके बावजूद भी आफिसर कहते हैं कि यह तो इसकी डयूटी है। ऐसी हालत में वह कैसे ईमानदार रह सकेगा? ये आफिसर ही उसको बईमान बनाते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि गृह मन्त्रालय को इस बात को देखना चाहिये—अगर गृह मन्त्रालय और उसके आफिसर प्रमाण चाहें तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूं।

यहां पर हर जगह अफसरशाही चल रही है और यह अफसरशाही गवर्नमेंट की दुश्मन है—इनमें ईमानदार बहुत कम मिलेंगे। वे लोग तो यही चाहते हैं कि किसी तरह से यह कांग्रेस गवर्नमेंट फेल हो जाय और उनकी अफसरशाही खूब चलती रहे। लेकिन उनको पता नहीं है अगर कांग्रेस सख्त हो गई तो फिर वे बाकी नहीं बचेंगे अफसरों का यह तरीका, जो शासन को चलाने का अंग्रेजों का तरीका है, समझता हूं कि इस में परिवर्तन करना चाहिए।

अंग्रेज यहां पर शासन करने आये थे वे हमको गुलाम बनाकर शासन करना चाहते थे लेकिन आज तो हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं, इसलिए इस पद्धति को बदलना चाहिए और जो ऊपर से नीचे तक फाइल का रगड़ा है वह बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह जो अफसरशाही है वह हमें फेल करना चाहती है। इसको अगर गृह मन्त्रालय ठीक नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? यह गृह मन्त्रालय का काम है। किसी और दूसरे मंत्रालय का काम नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरफ ध्यान दें और जो अफसरशाही चल रही है उसके विरुद्ध कड़े कदम उठाएं जायें तभी जाकर हमारा भला हो सकता है। जितने काम कांग्रेस कर रही है उस पर अगर सही मानों में अफसर साथ दें तो इस देश में कानून और व्यवस्था की जो खराब हालत है वह बिल्कुल ठीक हो सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा इसकी तरफ आप ध्यान दें और जो अफसर सरकार विरोधी हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लें। मैं तो कहता हूं कि यहां का कानून ही अजीब है जब तक कोई आदमी रंगे हाथों न पकड़ा जाये तब तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकती है चाहे कितना ही गवर्नमेंट के खिलाफ वह काम करे। मैं कहता हूं ऐसे आदमियों के खिलाफ मुकदमे चलाये जायें, उन्हें डिसमिस किया जाये और यदि सजा भी देनी चाहें तो सजा भी देनी चाहिए।

SHRI V. K. KRISHNA MENON (Trivendrum): I intervene for the first time in the debate on the Demands for Grants of the Home Ministry under a sense of compulsion; I want to say that I shall not go into the details of the administration or various other factors connected with it which are uppermost in the minds of hon. Members; but I propose to deal with four matters, and the fundamental principles behind them. One is the regard that the Home Ministry must have to the fact

[Shri V. K. Krishna Menon]

that this country is a signatory to the Declaration on Human Rights and the Geneva Conventions in regard to the treatment of people engaged in civil tumult. The second is the principles on which police may be allowed to use force or suffer penalties if they did the other way. The third is in regard to the Central Reserve Police and the Fourth is the Defence of India Act and the rules thereunder.

I only mention the first point and leave it there, as it is not possible to elaborate it within the time allotted. With regard to the second point, namely the use of force, I merely enunciate the principle that the policeman, as a member of our community, as a citizen, has no more rights and no less rights than anybody else. If he uses force against somebody which he should not do, he ought to be prosecuted or hanged like everybody else. Use of force is justified in self-defence; for example, when he happens to be in a blind alley and cannot get away and the crowd gets at him and he has to use force in his own defence, just as a private citizen can. Or, it can be done in order to prevent a greater harm; shall we say when a person is levelling a weapon against somebody else, he may strike off his hand.

But the basic principle, basic function of the police is not punitive. Even if he were to get a murderer, he has no business to beat him. What punishment he should receive is a matter for the Judge. In that situation, getting away from the abstract proposition, I want to say that the mild weapon that the policeman carries, the lathi, is a very heavy affair, with two netted hooks capable of inflicting severe harm and more often doing worse. I have seen cases in hospitals in U.P., Kerala, and other places where they have broken limbs and stout bones. Therefore, I think it is time that the Home Ministry inculcated into their most important arm the idea that citizens are entitled not only to humane trestment but a treatment in which there is regard for their self-respect.

What happens, for instance? A student goes in a bus; some other students stop the bus. Everybody gets down and there is a general melee; the innocent student also gets down and runs; the police chase him and beat him. What for? The idea is not to prevent greater harm, but to strike terror into the hearts of people. The Home Ministry would say that the beating is done in the fleshy part of the body. I won't agree with it. But, I can understand that the pain might have some effect and so on and so forth. It is always inflicted on the sensitive parts, that is, the skull or the bone of the fellow whereby permanent harm is done. This is a very serious matter. We see on the streets the kind of walking men—the magistracy—who go on inflicting harm.

In a civilised country where we have Parliamentary institutions, the police men would be equally guilty if they do this kind of thing. It can be elaborated very much, but you won't allow me time to do so.

Now I come to the Central Reserve Police. I do not belong to the group who believe that the C.R.P. should not exist or it is unconstitutional or it should not be used in different parts of the country. But, I say that the Central Reserve Police cannot also go to the States except with the consent of the State concerned. Secondly, they go there to protect the union property and perhaps they go to guard the Union Ministers because they require very much guarding of themselves. The C.R.P. is a very essential element especially in a country like ours with all its ramifications. I do not want to take the position that the Central Government has not right to do so. They equally have an important duty to perform on our borders. In these areas they are stationed in this way. But, at the same time, for them to be stationed

there in this way would also be a very deplorable affair. Here is the reserve army to strike our people. It is true that the police force is also used in houses of education. We have also a large number of instances to show that violence is not only committed by the students but by others also—the forces of law and order—and laboratories are destroyed by them and teachers have been shot at—it did happen once in Jammu and things of that character.

I think that it is time that the Ministers concerned at the political level should try to infuse into the minds of the people that they are not police dogs but they are policemen and see that they are not let loose. I do not want to take much time on this because there are other imporant matters on which I want to speak.

Regarding the Defence of India regulations, we have two measures of preventive detention—one is the Maintenance of Internal Security Act and the other is the Defence of India Regulations. I wanted to deal with them at length, but since there is no time I want to make it as short as possible. The Defence of India Act was promulgated on 4th of December, 1971. Under Section 1 sub-section (3) it has been laid down that it will continue for the period of emergency plus six months. Indeed the period of emergency is not any calendar period. This is the period which the Executive, either by its sweet will or by its wisdom or otherwise, decides. There is no definite period yet. The emergency will continue. The Maintenance of Internal Security Act, Act No. 26 of 1971, was enacted on 2nd July, 1971 by this Parliament. Now, on account of the amendment of this Act to the Defence of India Act, the time-limit has been taken away. There is no timelimit provided for in the Act. For all time to come, this remains a part of the general law of the country. It lasted for one year. It provided for imprisonment for one year. This also has been cancelled out.

Like the regulations of 1803, it is not that the people can be detained for a long time. Now, I come to the amendment to the Defence of India Act. I would speak out quickly as to what has been done. A new Sec. 17A has been inserted into the Maintenance of Internal Security Act. The result of that is that the limit of detention has been increased from one to three years. Formerly, it was for one year only. Now, under the Maintenance of Internal Security Act, it has been increased to three years. The Adisory Board, instead of having to consider it in three months time can now take 21 months. That means, a man can be put into prison and there is no obligation for the Advisory Board to intervene before 21 months. They may do it, but there is no obligation. He can be imprisoned without even this farcial trial of Star Chamber for 21 months.

Power has been delegated under this amendment to smaller officials. I am not saying that a minister is a super man and the magistrate is inferior. But it so happens that with the status, powers and position of the hierarchy this power has been transferred to smaller officials without any guidelines. Parliament has abrogated its legislative functions. The Constitution says that the principles under which this shall be exercised must be laid down. But we have laid down no principles, with the result a magistrate can send a particular person to prison for no reason. These reasons cannot be questioned in court. In other words, whenever he feels, he can do so, though I do not say he always does so. The sovereignty of this Parliament has been abrogated to officials without laying down any principles for guidance. This is unbridled power exercised by people on the spot who have to report to the State Government. Having reported to the State Government, there is a provision that it should be re-

[Shri V. K. Krishna Menon]

ported to the Central Government. But reporting to the Central Government is a very eseteric affair. Nobody knows it. The man in prison cannot find out whether it has been reported and what has been reported. No opportunity is given to him under the ordinary conditions of natural justice to make a representation or be told what it is. This is again a violation of the Constitution. The relevant article of the Constitution has been intended as a safeguard for the citizen. Those safeguards have all been taken away and we have a situation where anybody can be put into prison for any number of years. What is more, a new provision has been introduced and the Calcutta High Court has struck down this provision for renewed detention which is not provided in the Constitution at all.

It is fashionable in this House sometimes to blame the judiciary for everything. The judiciary appears to me to be the only little protection we have these days against the excesses of the executive. No executive can be armed with excessive powers because my liberty and everybody's liberty is in danger. My liberty is as important and precious to me as anything else and I do hope that the Government will look into these provisions of the Maintenance of Internal Security Act and the Defence of India Act.

I would like to conclude by quoting two little passages. A few years ago this matter came up and a Supreme Court Judge, Mr. Justice Gajendragadkar said:

> "We come across orders of this kind by which citizens are deprived of their fundamental right of liberty without a trial on the ground that the Emergency proclaimed by the President in 1962 still continues and the powers conferred on the appropriate authorities by the Defence of India Rules justify the deprivation of such liberty. We feel rudely disturbed by the thought that continuous exercise of the very wide powers conferred by the Rules on the several authorities is likely to make the conscience of the said authorities"—if they have any conscience at all—"insensitive, if not blunt, to the paramount requirement of the Constitution that even during Emergency, the freedom of Indian citizens cannot be taken away without the existence of the justifying necessity specified by the Rules themselves."

I may add that in this matter, the court gave costs against the Government.

I would like to quote another passage from what Lord Atkin said, quoting Pollock, C.B.:

> "In England amidst the clash of arms the laws are not silent. They may be changed, but they speak the same language in war and in peace. It has always been one of the pillars of freedom, one of the principles of liberty for which, on recent authority, we are now fighting, that judges are no respecters of persons and stand between the subject and any attempted encroachments on his liberty by the executive, alert to see that any coercive action is justified in law. In this case, I have listened to arguments which might have been addressed acceptable to the Court of King's Bench in the time of Charles I."

I do not want to read the whole of it. He said:

> "I protest, even if I do it alone, against an uncontrolled power of imprisonment to the Minister."

This is the position I want to put before you. I hope I have tried to draw attention to the basic principles, that these policemen are not going to rule this country. Even bad Ministers are better than policemen.

SHRI A. P. SHARMA (Buxar): Sir, I stand to support the Demands of the Ministry of Home Affairs placed before this House. Sometimes I wonder how difficult the job of the Home Ministry is, in view of all provocations, difficulties and all kinds of situations being created by most of the opposition parties, whether freindly or unfriendly to the ruling party. Sometimes, even friendly parties, while extending their support wherever they like, try to interfere in the affairs of the Congress Party and try to dictate terms to the government of this country.

While criticising the working of the Home Ministry, some hon. Members have said that the police have not performed their duties properly and the CRP have not discharged their responsibilities properly. Some reference was also made to their behaviour with the people. There cannot be any difference of opinion on that question. But when such a situation is created where the police has to intervene, should we also not consider who are responsible for the creation of that situation and what is the duty of the policemen or people in charge of maintaining law and order? Therefore, it is unfair to criticise the police every time. Of course, whenever they commit excesses, proper action should be taken against them, for which there is a regular procedure. When they are found guilty, they should be punished. We are not here to defend the wrong acts committed by the police or anybody else in this country.

Here I want to refer to the speech of my hon. friend, Shri Bhupesh Gupta, in the other House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is against the rule. I would like to point out that under our rules no reference could be made to the proceedings of the other House, except when it is a definite statement of policy on the part of the Government.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI (Shajapur): It has appeared in the press.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He can refer to the newspaper reports, but not to the proceedings.

15 hrs.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam): Sir, on a point of order. Members in the other House are referring to the names of the Members of this House. Members in this House....

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are not concerned with what the other House does. If they do anything, it is their business. But, I think, we should keep to the traditions of the best of parliamentary practice. I have given my ruling.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: Sir, only a point of explanation. The Chairman of the other House should follow this precedent.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not here to comment on that.

SHRI A. P. SHARMA: Sir, while debating the Budget in the other House, it was said—I am only quoting what has already been reported in the newspapers. I will not mention the name. But, I am quoting the fact.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not mention the other House also.

SHRI A. P. SHARMA: It has been reported in the newspapers that certain Members of the friendly party of the Ruling Congress are very much worried as to what is happening in the Congress Party and they have taken upon themselves to decide as to who is progressive and who is not progressive in the Congress Party. Sir, I take a strong objection to this kind of activity by the Communist

[Shri A. P Sharma]

Party of India. Congressmen in this country, not only I alone, but most of my friends in the Congress Party, and as a matter of fact all of us, do not need a certificate from such parties who have been even opposed to the War of Independence in this country and today they have earned so much respectability that they give certificates to the Congressmen as to who is progressive and who is not progressive.

It has also been said that the result of the last Presidential Election would have been different if they had not supported the candidature of the present President. It is a fact that the opposition parties supported the candidature of the present President. But, what does it mean? What price they want to be paid for that? Do they want that publicly they should demonstrate against this Government, criticise this party, criticise the activities of the Prime Minister of this country and they should try to hobnob and create a situation as if they are going to guide the affairs of the Congress Party? I wanted to make a reference to this specially. That was the main purpose for my speaking on the Demands for grants of Home Ministry. This is also a kind of encroachment, a kind of interference in the political activities of the Congress Party in this country. This creates difficulties in the fields and in the political and social life of the country.

What happened the other day? There was a debate on ticketless travel and it was said that in certain parts of the country—especially the name of Bihar was mentioned—people travel without ticket. But, here, it was discussed openly in this House that lakhs of people came here. None of us are concerned about whether they came with ticket or without ticket. It is the concern of that party which organised the demonstration and it is the outlook of that party to see that people come with proper ticket and they also go back so. They should perform their duties lawfully. Whenever these people commit mistakes, they try to throw the blame on others and this is how this party is functioning in the name of progressivism.

This is how they function in the name of socialism, this is how they function in the name of workers and peasants. I do not want to go in their affairs. It was discussed in this House. I want to say that in future, I hope, they will mind their own business.

Lastly, I want to say one thing more. If they were so progressive, as they were parading themselves as socialists and if they say that they can maintain the unity of all the socialist forces in the country, why they divided their own party? What was the reason? Therefore, instead of looking at others, they should look to their own affairs. I hope, they will take lessons from their own activities instead of pointing fingers at others.

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Member, Mr. Krishna Menon, just now made certain observations about the police. While I agree with Mr. Krishna Menon that our police need to be trained, better educated, to exercise their discretion in given situations with greater care and caution, there is the other side of it also.

Certainly, I do not hold any brief for them. I do not mean to defend them. Certain excesses have taken place at certain places. But, frankly, what I feel is this. Most of us in the Parliament and outside are talking against the police. I believe, talking too much against the police on every occasion, in every situation, blaming them for everything that happens in the country, from a small offence which is committed by one person and is not detected for a few days to any big political development which takes

place as a result of which some problems of lawlessness are created, is not good. We blame the policeman on every occasion. We hold him responsible in every situation. We call him a symbol of terror; we call him a symbol of repression. In every situation, we call for a judicial inquiry. I want to be very candid about it. On the one hand, we expect the police to protect us; we expect the police to protect the society, in every situation, everywhere. I want to ask you candidly, if the police were to be withdrawn from the Parliament, will you be able to run this Parliament?

SHRI G. VISWANATHAN: Why not? (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: May I draw your attention that there are no policemen as such within the precincts of the Parliament House. If they are here, they are security guards under the control of Parliament.

SHRI H. K. L. BHAGAT: I shall correct myself. I thank you for your guidance. What I am saying is, if you keep policemen outside and, supposing, you withdraw them from outside.... (*Interruption*) I am a Member of Parliament as much as anyone else there. I have the right to have my say. What I feel is that what we are saying is demoralising the police force in the country. That is not a good situation for any country. Therefore, what I would suggest is that so far as police excesses are concerned, they deserve to be condemned and they deserve to be scrutinised but demoralising the police force is not a good sign for the country. Their lack of initiative will create greater problems for us. So, I would request the hon. Members to think of this side of the matter while they make their points.

Secondly, the Home Ministry is in a very peculiar situation. They are responsible for maintaining law and order. Their responsibility is to see that the country remains in order. The law and order is a subject within the jurisdiction of the State Government. Apart from that, what is happening? How does this lawlessness come in? If you look into the developments of the last one year, if you look into the situation of lawlessness created in the country, you will find that there are political reasons, political factors, political elements, behind it. We create conditions of lawlessness and then come and blame the Home Ministry for it, for not having done this or that, for sending the Central Reserve police force; if they do not send the CRP, they are condemned for it, and if they send, then also they are condemned. What I am submitting is that political reasons, political factors and political elements are responsible for the condition of lawlessness in the country. The Government in this country must, therefore, think whether the stage has not come that a Standing Commission should be appointed. That Commission should see if any one—whether in the Government or the ruling Party or of any other Party —is, by his action or deed, trying to provoke people to resort to violence, notice should be issued to him and if a *prima facie* case is found against him by the Commission, he should be suspended, and if evidence is forthcoming, the case should be reported to the President for his removal or for de-recognition of party if a party is involved. Certain people are trying to subvert democracy. I see in this House one or two members standing and shouting not caring for the Chair, not caring for the rules or procedure, and outside also the same thing is being done. Therefore, it is high time that such a Commission was appointed.

My hon. friend, Mr. Atal Bihari Vajpayee, was talking today in this House.—I am sorry I was not present when he talked—about *Vande Mataram*. *Vande Mataram* is a song which all of us, sitting on these benches, our colleagues, our leaders and patriots, have sung for almost the whole decade. We have respect for that song more than his Party which was no-

[Shri H. K. L. Bhagat]

where at the time when singing of *Vande Matharam* cost lives and sent people to gallows. I want to tell him that Jan Sangh is not yet reconciled even to the idea of our national independence. Even now, 15th August is not celebrated by them as a day of independence. Jan Sangh does not do it. They are still talking of Akhand Bharat, and they have never felt that we are a proud and progressing nation. I am saying a plain fact, absolutely plain fact. Not even one function has been organized by the Jan Sangh on 15th August when we became a free nation. Even, with great difficulty, technically, they reconciled to the national flag, but not in spirit. Technically, when RSS was banned, they gave an undertaking that they would respect the flag, but in effect and spirit, they as a party have not accepted this. (*Interruptions.*)

He was also talking of communalism of Muslim League. Communalism of Muslim League is deplorable indeed, is condemnable indeed; we do not defend it, we do not condone it. But I want to ask Mr. Vajpayee what is his Party doing except trying to create communalism in this country, trying to flame troubles, trying to create one trouble or the other. If Jan Sangh sheds its communalism, I am sure they would be doing a service to the country.

One word about Delhi. I would like to point out to the Home Minister that Delhi continues to suffer from multiplicity of authorities and agencies in Delhi as well as the Centre in various Ministries. Delhi problems do not get a co-ordinated attention. Delhi problems are delayed. So, I will request them to review the situation and create some kind of co-ordination and a focal point so that these problems can be dealt with more easily.

One word, I would finish. That is, so many bad incidents have taken place in the country.....

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Shameful incidents.

SHRI H. K. L. BHAGAT: Shameful enough, but it is even a greater shame to paint a bad picture of the whole country on the basis of a few incidents, which you are trying to do. I am really amazed. Now, Mr. Jyotirmoy Bosu picks up all the dust from outside and spreads it in this House —false, fabricated, meaningless and irrelevant things. I would request the hon. Minister.... (*Interruptions*)

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: You are creating dust outside..... (*Interruptions.*)

SHRI H. K. L. BHAGAT: Jagota brothers and their sister are their new gods and goddesses .... (*Interruptions*).

Lastly, I want to make one request to the Government. That is that they should try and salvage the opposition which is functioning in a manner that they are sinking every day and day by day into the depth of their opportunistic tactics. I would say that the Government should try to do something to salvage the Opposition which is so necessary for a democracy as the Opposition cannot salvage themselves.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): On a point of order, Sir. I do not to want to use harsh language about my colleague here. I do not want to call him a clown. He said that so many issues have been brought. Which one is he talking about, Sir? Is it Nagarwala episode or Maruti Ltd. or the Wanchoo report? Which one is he talking about?

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar): I rise to support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs. I am glad that the Department of Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been taken over by the Home Ministry. We have been trying for it for quite a long time. Sir, some-

times this department had been handled by the Law Ministry, sometimes by the Education and Social Welfare Ministry and sometimes by the other Ministry. Therefore, the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were not looked into properly.

Art. 16 of the Constitution—Fundamental Rights—I have no time to read it out. I would like to point out to the Home Minister—one is an experienced ex-Speaker of Rajasthan and the other is a worthy son of an illustrious father. Therefore, I am hopeful that they will try to ameliorate the conditions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Before coming to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I must not forget the reference made by the respected lady member, Shrimati Jyotsna Chanda. The language issue is a very serious and an emotional one. Language chauvinism I never support. I like and respect all the languages of India. I have learnt Hindi to the extent of 75 per cent. So also I know Bengali and Assamese as well, though I have a language of my own. To hate any language is not a healthy thing at all. Everybody should allow other languages to survive and develop.

Now, coming to the State of Assam, the present problem is not a new problem. This is a problem which has been there since 1961. Even during Nehru days it was there. There was a language riot in Assam and Pandit Nehru himself said in the Parliament and in the Central Hall that the Assamese has got every right to exist as they had been exploited by various sections of people from outside for ages and now they have come into their own right and they have every right to exist. There is commotion and emotion when the question of language comes.

There are 50 High Schools in the Brahmaputra valley with Bengali medium and these are all granted by the Government. Also there are number of Primary Schools with Bengali medium. I ask the lady Member as to where is the question of suppression and exploitation of the Bengali language.

About your own State Mr. Deputy-Speaker, your State is formed not on the question of language alone. This is formed on the basis of the strategic point of view. You know personally that whenever there was demand for Meghalaya, I opposed it; whenever there was demand for Mizoram, I opposed it. I opposed because I believe in the integration of the country.

I would now like to refer to the Chapter in the Fundamental Rights where there is provision made for employment with equality of opportunity for all citizens. This Article No. 16 of our Constitution alone could not justify the interest of S. C. and S. T. So, special provision had been made for the scheduled castes and scheduled tribes because they could not come up in competition. That is why Article 46 stands for the protection of the rights of the scheduled tribes people. I request Mr. Mirdha and Mr. Pant to hear what I say. Article 335 of the Constitution flouts and stands in the way. Please read that Article. It says:

> "The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

This is what stands in the way. The bureaucrats take the plea under this Article. Therefore I request the Government that this Article be amended. On the plea of this Article the bureaucrats take the opportunity to refuse to respect the provisions of Articles 16 and 46. That is why I say that this Article should be amend-

[Shri D. Basumatari]

ed. I am very glad that the Prime Minister has appointed a Parliamentary Committee, namely, the Committee for the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as watch dog Committee. You know about it. Sir, I had been the first Chairman of the Committee. I and the Members of the Committee know very well about this problem. Whenever we had opportunity to examine the witness who come from the departments, we found that these bureaucrats were most reluctant to respect the special provisions laid down in the Constitution to ameliorate the condition of these people. We want to ameliorate the condition of these people and we want *garibi hatao* and we want to achieve socialism. All this cannot be done unless and until the bureaucrats change their objective and change their mentality. I appeal to my hon. friends, Mr. Mirdha and Mr. K. C. Pant to consider this. I know that Government are trying their level best to do something for the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes in various ways. 482 tribal blocks have been started. I have visited almost all the tribal blocks in the country. What we found out was this. After the establishment of the tribal blocks and after roads had been constructed leading to tribal areas, as a result their lands had been taken out by the sahukars and money lenders. Not only that Sir, on the plea of establishment of industries, tribal people had been ousted from their homes and hearths. There is no provision to give them land for land, and also compensation. The compensation that is given to them differs from place to place. I have examined many cases. There is great discrimination in the case of compensation which they are getting. They are paying only the lowest. They are tribal and the scheduled castes people in the same area. So, I request the hon. Minister to look into this matter. I expect Mr. Pant and Mr. Mirdha to respect the feelings of scheduled castes and scheduled tribes. I request them to amend. Article 335 of the Constitution which is standing in the way, if they mean business.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Sulaiman Sait may speak for five minutes.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: I will take 10 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is to be noted. He will not speak on any other demand.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोट) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप का बहुत मशकूर हूं कि आपने होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पर मुझे अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया और जो कुछ गलतबयानी यहां पर मेरी पार्टी के बारे में, हमारे ममायल के बारे में और हमारी पालिसी के बारे में की गई है, उस की सफाई का मौका दिया है। मैं एक बात यह जरूर कहूंगा कि जहां तक आजादी के 25 साल का ताल्लुक है, मैं इस की तफसील में जाना नहीं चाहता। अक्लियत की हैसियत से हम पर जो जुल्म किए गए, हम को जिस तरह सितम का निशाना बनाया गया यह एक दास्तान है। हमारे हाल की तर्जुमानी इस तरह से की जा सकती है :

हम वफा करते रहे और वह जफा करते रहे।
अपना अपना फर्ज हम दोनों अदा करते रहे।

बात यह है कि जहां तक हमारा ताल्लुक है। हम दिल से चाहते हैं और पूरे खुलूस से चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के जितने फिरके हैं उन में आपस में मुफाहमत हो, आपस में एक दूसरे के साथ मुहब्बत हो, आपस में हमदर्दी हो और हम सब मिल कर हिन्दुस्तान को बना सकें ताकि हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क बन सके जो हम सब के लिए काबले फख्र हो सके। लेकिन हमें दुख होता है जब हम

यह देखते हैं कि यहां पर मुख्तलिफ इकाइयां जो हैं, मुख्तलिफ अक्लियतें जो हैं, जो उन का एक तसव्वुर है, उन के अकायद हैं, उन का कल्चर है, उन की तहजीब है, इन तमाम को जो मिटा देने की बातें की जाती हैं, और मतालबा किया जाता है कि इन को मिटा देने के बाद ही हमको वफादार तसव्वुर किया जायेगा, हम उस की मुखालिफत करते हैं। हमारी जो इकाई है, हमारी जो अलग हैसियत है, हमारा जो कल्चर है, हमारे अकायद तसव्वुरात हैं उस को खत्म करने के लिए हम किसी तरह तैयार नहीं हैं। उस को बरकरार रखते हुये कौमी मसायल में हम मुल्क का साथ देने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।

यह कहना कि हमारी पार्टी एक कम्युनल आर्गनाइजेशन है, फिरकेदाराना जमात है यह एक इन्तहाई गलत बात है। जहां तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है यह एक नेशनल आर्गेनाइजेशन है माइनारिटीज की, अक्लियतों की यह एक नेशनल माईनारिटी आर्गेनाइजेशन है। मेरे दोस्त भगत साहब ने जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, यह कहा कि मुस्लिम लीग एक कम्युनल आर्गनाइजेशन है। लेकिन मैं उन से कहूंगा कि वह श्रीमती इन्दिरा गांधी से पूछ लेते कि मुस्लिम लीग का क्या रोल रहा है, मुस्लिम लीग ने किस तरह साथ दिया है मगरिबी बंगाल और केरल में किस तरह मुस्लिम लीग को प्राइम मिनिस्टर ने ही एक कौमी आर्गनाइजेशन करार दिया है ?... (**व्यवधान**) हम यह पूरे यकीन के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ समझते हैं कि हमारी जमात एक कौमी जमात है। आजादी से लेकर हमने आज तक 25 साल से आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मुल्क के खिलाफ हो या जो मुल्क के बाशिन्दों के मफाद के खिलाफ हो। हम हर एक के साथ दोस्ती चाहते हैं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, अदावत नहीं। हमारा कल्चर, हमारी तहजीब किसी पर थोपना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमें दूसरों के साथ बराबर का हिस्सा मिले। हम भी इस मुल्क के बाशिन्दे हैं, हमें भी इस मुल्क की तरक्की में अपना फर्ज अदा करने का पूरा हक़ मिलना चाहिये।

यहां पर मुखतलिफ बातें कही गई, आदादो-शुमार पेश किये गये कि मुसलमानों को मुलाजमतों में उन को इस तरह पूरा हिस्सा नहीं मिलता। होम डिपार्टमेंट है, एक्सटनल अफसर्ज डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सी०आर०पी० है, फौज हैं, मुखतलिफ किस्म के शोबे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इन में कितने मुसलमान हैं, कहां तक उनको नौकरियों में लिया जाता है, कहां तक उनको मुनासिब और मुनसफाना हिस्सा दिया गया ? एक बार हमारे साबिक सदर डा० जाकिर हुसैन साहब ने कहा था, कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों की बड़ी अजीब पोजीशन है, वह हकूमत में बराबर का साथी है, एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे शोबों में उस का पूरा हक़ है। लेकिन, जनाब, ऐसा कह देने से कुछ नहीं होता, अमली तौर पर मुसलमानों को मुलाजमतों में जगह मिलनी चाहिये ताकि कहा जा सके कि अमली तौर पर हिन्दू और मुसलमान इस मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन में बराबर के हक़दार हैं, हिस्सेदार हैं। लेकिन आज हकीकत यह नहीं है। 12 फी सदी मुसलमानों को 1 फी सदी मुलाजमत भी नहीं मिलती। हकीकत में हिन्दू और मुसलमान एक ही जिस्म के दो आंखें हैं, एक आंख को फोड़ देना और कह देना कि मुल्क तरक्की कर रहा है—यह एक अजीब बात होगी, जिस को समझा नहीं जा सकता।

जहां तक होम मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स का ताल्लुक है—मुझे यह कहना है कि आये दिन फिसादात होते रहते हैं हरिजनों पर जुल्म किये जाते हैं, जुबान के मसले को लेकर फिसादात होते हैं, इलाकाई तौर पर फिसादात

[श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ]

होते हैं। जब यह कुछ हो रहा है—फिसादात हो रहे हैं, जानोमाल का तहफ्फुज नहीं है, यह कहना कि हम गलत बयानी से काम लेते हैं हालात को गलत तौर पर पेश करते हैं—मुनासिब नहीं है। अभी भगत साहब मैंने जो कुछ कहा, वह गलत है। जब तक इस मुल्क का एक एक बाशिन्दा भी यह महसूस करे कि उस की जानो माल खतरे में हैं, मैं समझता हूं कि होम मिनिस्ट्री अपने फर्ज को अदा नहीं कर रही है। जिस दिन इस मुल्क का हर शख्स महसूस करे कि हम अमन के साथ रहते हैं, चैन के साथ रहते हैं, वह दिन हिन्दुस्तान के लिये जन्नत बन सकता है और हमें इस के लिये कोशिश करनी चाहिये। आज हमारे पास जासूसी का महकमा है, पुलिस है, पी०ए०सी० है, सी० आर०पी० है, फौजें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी फिसादात पर काबू नहीं पाया जाता—अजीब बात है। फिसादात के लिये महीनों तैयारियां होती हैं। इण्टीग्रेशन कान्सिल में एक सिफारिश की गई थी कि जहां फसादात होते हों वहां मुकामी हुक्काम के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। यह जरूरी है कि जहां फसाद हों वहां जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिन्टेंडेण्ट, उन के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये, लेकिन क्या कहीं कोई कार्यवाही की गई। नेशनल इण्टीग्रेशन कान्फ्रेंस होती है, होम-मिनिस्ट्री के सैक्रेटरीज की कान्फरेंस होती हैं, लेकिन कुछ इकदाम नहीं किया जाता। मैं चाहता हूं कि ट्रिब्यूनल्स बनाई जानी चाहियें ताकि जल्द से जल्द शरारत पसन्द अनासिर को सजा दी जाय। फसादात में आज तक हजारों आदमी मारे गये—कितने मुकदमें चले, किन को सजायें मिलीं, कितनों को सूली पर चढाया गया। हम यह नहीं चाहते कि अगर हम जिम्मेदार हैं, अगर हम ने गल्ती की है तो हमें छोड़ दिया जाय, हमें गोली मार दीजिये, हमें कोई इन्कार नहीं होगा, लेकिन अगर मुल्क में फिरकापरस्त अनासिर है, जिन्होंने लोगों को कत्ल किया है, जो लोगों की जान लेते हैं, उन के खिलाफ जब कार्यवाही न की जाय। इस लिये एक अकलियत के तबके के नुमाइन्दे की रहियत से आप से यह सवाल करने का मुझे हक हासिल है कि मैं मुतालबा करूं कि ट्रिब्यूनल कायम करनी चाहियें, ऐसी मिली जुली पुलिस फोर्स होनी चाहियें जिसमें सब फिरके के लोग हों। जब फिसादात हों तो वहां पर मिलीजुली पुलिस जाये जो अमन को कायम रख सकें।

आज कल फिसादात में एक नई चीज पैदा हो रही है—हम देखते हैं कि पिछले दिनों जो फिसादात हुए, जैसे फीरोजाबाद में और बनारस में। अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नया एक्ट पास किया गया, जो मुसलमानों के लिए काबिलेकुबूल न था, वहां पर एहतिजाज के तौर पर मुसलमानों ने काले झण्डे लगाये, काले बैज बांधे—जो अपनी मुखालफत के इजहार करने का एक जम्हूरी तरीका है, उस के जरिये उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन वहां क्या हुआ ? पुलिस ने गोली चलाई, मुसलमानों को मारा गया, खून बहाया गया, पी०ए०सी० ने घरों के अन्दर जा कर लोगों को मारा, लूट मार की, यहां पर सब कुछ बरबादी पुलिस और पी०ए०सी० और सी०आर०पी० ने की, आजकल जहां कहीं फिसादात हुए हैं, सब से ज्यादा लूट मार करने वाले पी०ए०सी० के लोग होते हैं। क्या यह हकूमत की जिम्मेदारी नहीं है ? अब तक 240 फिसादात हुए हैं, जिनका जिक्र होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में किया गया है। असम में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, मंसूर में हुए, महाराष्ट्र में हुए, अभी अभी राजस्थान में नागौर में हुए। यह झगड़ा कैसे और क्यों हुआ—यह एक जाती झगड़ा था, इस में एक शख्स मारा गया, दूसरे दिन पुलिस ने उस की अर्थी का जुलूस निकालने की इजाजत दे दी, जिस के नतीजे में फसाद हो गया,

वहां मकान लूटे गये, लोगों को मारा गया, तबाह किया गया, मस्जिदों पर हमला किया गया और उन्हें तबाह किया गया और वहां टेन्शन अभी तक मौजूद है। जब टेन्शन मौजूद था तो पुलिस को मरे हुए शख्स की लाश का जुलूस में जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। अब हुकूमत को जिन का नुक्सान हुआ है उनको मुआवजा अदा करना चाहिए।

अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बहुत से मसाइल खड़े किये, उर्दू जबान का जिक्र आया, उनकी बड़ी जोशीली तकरीर थी. मैं यहां जोशीली और गरम तकरीर नहीं करना चाहता, ठण्डे दिल के साथ आप से अर्ज करना चाहता हूं कि आप बड़े भाई हैं, हमारे एहसासात को समझना आप का फर्ज है। मैं तो यह कहूंगा किसी भी हुकूमत की, जम्हूरियत की कसौटी उस मुल्क के अकलियतों का इत्मिनान है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मुल्क की अकलियतें मुतमईन हों, सैटिस्फाइड हों—यह सब से बड़ी चीज है। और यही हकूमत की कामयाबी की बुनियाद है।

उर्दू जुबान का जहां तक ताल्लुक है—हम नहीं कहते कि उर्दू जुबान मुसलमानों की जुबान है, उर्दू हिन्दुस्तान की कौमी जुबान है। सर तेज बहादुर सप्रू ने कहा था कि हिन्दू और मुसलमानों की मुशतर्का मीरास है। आज अगर हम मुखतलिफ टोलियों के बजाय एक जगह बैठना चाहते हैं तो कोई जुबान हिन्दुस्तान को अगर मुत्तहिद रख सकती है—वह उर्दू जुबान हैं। इस लिये यह कौमी जुबान है।

यहां पर वन्दे मातरम के बारे में कहा गया—मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। बहुत सी बातें कही गई, जजबात उभारने की कोशिश की गई—लेकिन सवाल यह है कि बम्बई कारपोरेशन के इन्तखाबात में यह मसला लेकर किसने जजबात को उभारा? 25 साल हिन्दुस्तान को आजाद हुए हो गये, आज तक यह सवाल नहीं था, किस ने खड़ा कर दिया, किस ने जजबात को उभारने की कोशिश की—एक कांग्रेसी ने की, महाराष्ट्र की कांग्रेस ने सियासत, वहां की वजारत इस के लिए जिम्मेदार है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हू जब कांस्टीचुएन्ट असेम्बली शुरू हुई थी, उस का आगाज वन्दे-मातरम् से हुआ था, और इकतिताय सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तान हमारा—उस गीत से हुआ था। इसके बाद जन गण मन को कौमी तराना करार दिया गया। रविन्द्रनाथ, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। उन्होंने भी कहा था—कि वन्दे मातरम् के मामले में किसी के साथ जब्र न किया जाए। टैगोर ने कहा था कि मैं ब्रह्म समाजी हूं—लेकिन वन्दे मातरम् के मामले में जबरदस्ती का कायल नहीं। हम कहते हैं कि हम इस गाने की इज्जत करते हैं, हमें इस के लिए पूरा अहतराम है, लेकिन हम पर गाने के लिए जब्र न किया जाए। मेरे बादराने वतन के ख्यालात का पूरा अहसास है जैसा कि कहा गया है :

ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हर दम,
अनीस ठेस न लग जाए, आबगीनों को।

हम फिर यह कहते हैं कि हम अहतराम करेंगे, लेकिन जब्र न कीजिये, कम्पलशन न कीजिये। यही हमारा मुतालबा है।

अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला है। वाजपेयी साहब ने पूछा था कि अक्लीयती किरदार क्या है? जब यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नया बिल पेश था और उस पर बहस हुई थी, तब मैंने तफसील के साथ बताया था कि अक्लीयती किरदार क्या है। कैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, किस किस ने कुरबानियां दीं, एन्ड्राउमेन्ट्स कायम किये, इमारतें बनाई, पैसा दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए कायम किया, लेकिन

[श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ]

औरों के लिए दरवाजे बन्द नहीं किये । उस यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट राजा महेन्द्र प्रताप सिंह निकले थे । चन्द साल पहिले मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलसिले सिफारिशात करने चैटर्जी कमीशन बैठाया गया, उसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खास किरदार को सामने रखते हुए सिफारिश की कि वहां पर 35 परसेन्ट नान-मुस्लिम और 65 परसेन्ट मुस्लिम तुलबा होने चाहिए—उन्होंने यह तनासुब बताया था । हम यह चाहते हैं कि जिस चीज को हम ने कायम किया था, अपने खूने-जिगर से सींचा, 100 साल तक पाला-पोसा, उस पर हमारा कन्ट्रोल रहे और यूनिवर्सिटी के तुलबा की तादाद में इसाल्जा की तादाद में मुसलमानों की अक्सरियत रहे ।

जहां तक मुसलमानों की इक्सादी हालत का सवाल है, तालीमी हालत का सवाल है—वह आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं । वाजपेयी जी ने कहा कि अकलियतें कुछ भी नहीं हैं । यह गलत है । अकलीयतें हैं, इस मुल्क के सैकुलर करेक्टर में उसके लिए जगह है, फन्डामेन्टल राइट्स हैं, सब कुछ है, इस से इन्कार नहीं किया जा सकता । इस देश में सेक्युलेरिज्म है और इसी की बुनियाद पर हम इस मुल्क में अपना हक चाहते हैं जो कांस्टीट्यूशन में फंडामेन्टल राइट्स दिये हुए हैं । उम्मीद है कि वाजपेयी जी इस हकीकत को समझाने की कोशिश करेंगे । वरना मैं कहूंगा :

अगर अब भी नहीं समझे
तो फिर तुमसे खुदा समझे ।

شری ابراهیم سلیمان سیٹھ (کوزی

کوڈ) : سبھاپتی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں - کہ آپ نے ہوم منسٹری کی رپورٹ پر مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقعہ دیا - اور جو کچھ غلط بیانی یہاں پر میری پارٹی کے بارے میں - ہمارے مسائل کے بارے میں اور ہماری پالیسی کے بارے میں کی گئی ہے اس کی صفائی کا موقعہ دیا ہے - میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جہاں تک آزادی کے ۲۵ سال کا تعلق ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا - اقلیت کی حیثیت سے ہم پر جو ظلم کئے گئے - ہم کو جس طرح ستم کا نشانہ بنایا گیا - وہ ایک داستان ہے - ہمارے حال کی ترجمانی اس طرح سے کی جا سکتی ہے:

ہم وفا کرتے رہے اور وہ جفا کرتے رہے
اپنا اپنا فرض ہم دونوں ادا کرتے رہے

بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم دل سے چاہتے ہیں اور پورے خلوص سے چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے جتنے فرقے ہیں ان میں آپس میں مفاہمت ہو - آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو - آپس میں ہمدردی ہو - اور ہم سب ملکر ہندوستان کو بنا سکیں - تاکہ ہندوستان ایک ایسا ملک بن سکے جو ہم سب کے لئے قابل فخر ہو سکے - لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے جب

پوچھہ لیتے کہ مسلم لیگ کا کیا رول رہا ہے - سلم لیگ نے کس طرح ساتھ دیا ہے - مغربی بنگال اور کیرل میں کس طرح مسلم لیگ کو برائم منسٹر نے ایک قومی آرگنائزیشن قرار دیا- ہم یہ پورے یقین کے ساتھ - پوری دیانتداری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت ایک قومی جماعت ہے آزادی سے لے کر ہم نے آج تک ۲۵ سال سے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو یا جو ملک کے باشندوں کے مفاد کے خلاف ہو- ہم ہر ایک کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں- کسی کے ساتھ دشمنی نہیں - عداوت نہیں - ہمارا کلچر - ہم تہزیب کسی پر تھوپنا نہیں چاہتے - ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ برابر کا حصہ ملے - ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں - ہمیں بھی اس ملک کی ترقی میں اپنا فرض ادا کرنے کا پورا حق ملنا چاہئے -

یہاں پر مختلف باتیں کہی گئیں - اعداد و شمار پیش کئے گئے کہ مسلمانوں کو ملازمتوں میں ان کا پورا حصہ نہیں ملتا - ہوم ڈپارٹمنٹ ہے - ایکسٹرنل افیر ڈپارٹمنٹ ہے - ایڈمنسٹریشن ہے - پولس ہے - سی - آر - پی ہے فوج ہے - مختلف قسم کے شعبے ہیں - ڈیپارٹمینٹس ہیں - آن میں کتنے مسلمان ہیں - کہاں تک ان کو نوکری میں لیا جاتا ہے -

ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مختلف اکائیاں جو ہیں - مختلف اقلیت جو ہیں - جو ان کا ایک تصور ہے ان کے عقائد ہیں - ان کا کلچر ہے - ان کی تہزیب ہے - ان تمام کو جو مٹا دینے کی باتیں کی جاتی ہیں - اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کو مٹا دینے کے بعد ہی ہم کو وفادار تصور کیا جائیگا- ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں - ہماری جو اکائی ہے - ہماری جو الگ حیثیت ہے - ہمارا جو کلچر ہے - ہمارے عقائد، تصورات ہیں - اس کو ختم کرنے کے لئے ہم کسی طرح تیار نہیں - اس کو برقرار رکھتے ہوئے قومی مسائل میں ہم ملک کا ساتھہ دینے کے لئے - ملک کی ترقی کے لئے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں -

یہ کہنا کہ ہماری پارٹی ایک کمیونل آرگنائزیشن ہے - فرقہ وارانہ جماعت ہے - یہ ایک انتہائی غلط بات ہے - جہاں تک میری پارٹی کا تعلق ہے وہ ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے مائنورٹیز کی، اقلیت کی، یہ ایک نیشنل پارٹی آرگنائزیشن ہے - میرے دوست بھگت سنگھ صاحب نے جو کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں - یہ کہا کہ مسلم لیگ ایک کمیونل آرگنائزیشن ہے - لیکن میں ان سے کہونگا کہ وہ شریمتی اندرا گاندھی سے

کہاں تک ان کو مناسب اور منصفانہ حصہ دیا گیا ہے - ایک بار ہمارے سابق صدر ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بڑی عجیب پوزیشن ہے - وہ حکومت میں برابر کا ساتھی ہے - ایڈمنسٹریشن اور دوسرے شعبوں میں اسکا پورا حق ہے - لیکن جناب ایسا کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا - عملی طور پر مسلمانوں کو ملازمتوں میں جگہ ملنی چاہئے - تاکہ کہا جا سکے کہ عملی طور پر ہندو اور مسلمان اس ملک کے ایڈ منسٹریشن میں برابر کے حقدار ہیں - حصے دار ہیں - لیکن آج حقیقت یہ نہیں ہے - بارہ فیصدی مسلمانوں کو ایک فیصدی ملازمت بھی نہیں ملتی - حقیقت میں ہندو اور مسلمان ایک ہی جسم کی دو آنکھیں ہیں - ایک آنکھ کو پھوڑ دینا اور کہہ دینا کہ ملک ترقی کر رہا ہے - یہ ایک عجیب بات ہوگی - جس کو سمجھا نہیں جا سکتا -

جہاں تک ہوم منسٹری کی ڈمانڈ کا تعلق ہے مجھے یہ کہنا ہے کہ آئے دن فسادات ہوتے ہیں - ہریجنوں پر ظلم کئے جاتے ہیں - زبان کے مسئلے کو لیکر فسادات ہوتے ہیں - علاقائی طور پر فسادات ہوتے ہیں - جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے - فسادات ہو رہے ہیں - جان و مال کا تحفظ نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم غلط بیانی سے کام لیتے ہیں حالات کو غلط طور پر پیش کرتے ہیں - مناسب نہیں ہے - ابھی بھگت صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے - جب تک ملک کا ایک باشندہ بھی یہ محسوس کرے کہ اس کی جان - اس کا مال خطرے میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہوم منسٹری اپنے فرض کو ادا نہیں کر رہی - جس دن اس ملک کا ہر شخص محسوس کرے کہ ہم امن کے ساتھ رہتے ہیں - چین کے ساتھ رہتے ہیں - واقعی وہ دن ہندوستان کے لئے جنت بن سکتا ہے - اور ہمیں اس کے لئے کوشش کرنی چاہئے - آج ہمارے پاس جاسوسی کا محکمہ ہے - پولس ہے - فوجیں ہیں - سب کچھ ہے لیکن فسادات پر قابو نہیں پایا جاتا - عجیب بات ہے - فسادات کے لئے مہینوں تیاریاں ہوتی ہیں - نیشنل انٹیگریشن کونسل میں سفارش کی گئی تھی کہ جہاں فسادات ہوتے ہیں وہ مقامی حکام کے خلاف کارروائی کرنی چاہئے - یہ ضروری ہے کہ جہاں فساد ہو وہاں لوکل ایڈمنسٹریشن ہے - جیسے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ - سپرنٹنڈنٹ پولس ان کے خلاف کار روائی ہونی چاہئے - لیکن کیا کہیں کوئی کارروائی کی گئی نیشنل انٹیگریشن کانفرنس ہوتی ہے - ہوم منسٹری کے سیکریٹریز کی کانفرنس ہوتی ہے - لیکن

کچھ اقدام نہیں کیا جاتا - میں چاہتا ہوں کہ ٹریبونل بٹھائی جانی چاہیئں - تاکہ جلد سے جلد شرارت پسند عناصر کو سزا دی جائے - فسادات میں آج تک ہزاروں آدمی مارے گئے - کتنے مقدمے چلے - کن کو سزائیں ملیں - کتنوں کو سولی پر چڑھایا گیا - ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر ہم ذمہ وار ہیں - اگر ہم نے غلطی کی ہے - تو ہمیں چھوڑ دیا جائے - ہمیں گولی مار دی جائے - ہمیں کوئی انکار نہیں ہوگا لیکن اگر ملک میں فرقہ پرست عناصر ہیں جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے - جو لوگوں کی جانیں لیتے ہیں - ان کے خلاف جب کارروائی نہ کی جائے- اس لئے ایک اقلیت کے طبقے کے نمائندے کی حیثیت سے آپ سے یہ سوال کرنے کا - مجھے حق حاصل ہے - کہ میں مطالبہ کروں کہ ٹریبونل قائم کرنے چاہئے - ایسی ملی جلی پولس فورس ہونی چاہئے - جس میں سب فرقے کے لوگ ہوں جب فسادات ہوں تو وہاں پر جائے جو امن قائم رکھ سکے -

آج کل فسادات میں ایک نئی چیز پیدا ہو رہی ہے - ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو فسادات ہوئے- جیسے فیروزآباد میں اور بنارس میں- علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نیا ایکٹ پاس کیا گیا - جو مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہ تھا - وہاں پر احتجاج کے طور پر مسلمانوں نے کالے جھنڈے لگائے- کالے بیج باندھے - جو اپنی مخالفت کے اظہار کرنے کا ایک جمہوری طریقہ ہے - اس کے ذریعے انہوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کی - لیکن وہاں کیا ہوا - پولس نے گولی چلائی - مسلمانوں کو مارا گیا - خون بہایا گیا - پی اے سی نے گھروں کے اندر جا کر مارا - لوٹ مار کی - یہاں پر سب کچھ بربادی پولس اور CRP اور PAC نے کیا - آجکل جہاں کہیں فساد ہوتے ہیں - سب سے زیادہ لوٹ مار کرنے والے پی اے سی کے لوگ ہوتے ہیں - کیا یہ حکومت کی ذمہ واری نہیں ہے - اب تک ۲۸۰ فسادوں میں جن کا ذکر ہوم منسٹری کی رپورٹ میں کیا گیا ہے - آسام میں ہوئے - یو پی میں ہوئے - میسور میں ہوئے - مہاراشٹر میں ہوئے - ابھی ابھی راجستھان میں ناگور میں ہوئے - یہ جھگڑا کیسے اور کیوں ہوا - یہ ایک ذاتی جھگڑا کیسے اور کیوں اس میں ایک شخص مارا گیا - کہا - دوسرے دن پولس نے ایک ارتھی کا جلوس نکالنے کی اجازت دے دی-جس کے نتیجے میں فساد ہو گئے وہاں مکان لوٹے گئے- لوگوں کومارا گیا-تباہ کیا گیا اور مسجدوں پر حملہ کیا گیا - اور ہمیں تباہ کیا گیا اور وہاں ٹینشن

اگر متحد رکھ سکتی ہے وہ اردو زبان ہے - اس لئے یہ قومی زبان ہے -

یہاں پر بندے ماترم کے بارے میں کہا گیا ہے - میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا بہت سی باتیں کہی گئی ہیں - جزبات ابھارنے کی کوشش کی گئی - لیکن سوال یہ ہے کہ بمبئی کارپوریشن کے انتخاب میں یہ مسئلہ لیکر کس نے جزبات کو ابھارا - ۲۵ سال ہندوستان کو آزاد ہوئے ہو گئے - آج تک یہ سوال نہیں تھا - کس نے کھڑا کیا - کس نے جزبات کو ابھارنے کی کوشش کی ایک کانگریس نے کی - مہاراشٹر کی کانگریس نے - وہاں وزارت اس کے لئے ذمہ دار ہے - اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں - جب کانسٹیچوینٹ اسمبلی شروع ہوئی تھی - اس کا آغاز بندے ماترم سے ہوا تھا - اور اختتام سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا - اس گیت سے ہوا تھا اس کے بعد جن گن من کو قومی ترانہ قرار دیا گیا - رابندرناتھ ، گاندھی جی کو ہم راشٹر پتا کہتے ہیں - انہوں نے بھی کہا تھا کہ بندے ماترم کے معاملے میں کسی کے ساتھ جبر نہ کیا جائے - ٹھاکور نے کہا تھا کہ میں برہم سماجی ہوں - لیکن بندے ماترم کے معاملے میں زبردستی کا قائل نہیں - ہم کہتے ہیں کہ ہم اس گانے کی عزت کرتے ہیں - ہمیں اس کے لئے پورا احترام ہے - لیکن ہم پر گانے کے لئے جبر نہ کیا جائے -

ابھی تک موجود ہے - جب ٹینشن موجود تھا تو پولس کو مرے ہوئے شخص کی لاش کا جلوس لے جانے کی اجازت نہیں دینی چاہئے تھی - جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا - اب حکومت کو جن کا نقصان ہوا ہے - معاوضہ ادا کرنا چاہئے - اٹل بہاری واجپئی صاحب نے بہت سے مسائل کھڑے کئے ہیں اردو زبان کا ذکر آیا - ان کی بڑی جوشیلی تقریر تھی - میں یہاں جوشیلی اور گرم تقریر نہیں کرنا چاہتا - ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں - کہ آپ بڑے بھائی ہیں - ہمارے احساسات کو سمجھنا آپ کا فرض ہے - میں تو یہ کہوں گا - کہ کسی بھی حکومت کی کسوٹی اس ملک کے اقلیتوں کا اطمینان پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا ملک کی اقلیتیں مطمئن ہیں - سیٹسفائڈ ہیں ۔ وہ سب سے بڑی چیز ہے - اور یہی حکومت کی کامیابی کی بنیاد ہے ۔

اردو زبان کا جہاں تک تعلق ہے - ہم نہیں کہتے کہ اردو زبان مسلمانوں کی زبان ہے - اردو ہندوستان کی قومی زبان ہے - سر تیج بہادر سپرو نے کہا تھا کہ یہ ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے ۔ آج اگر ہم مختلف ٹولیوں کی بجائے ایک جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو کوئی زبان ہندوستان کو

میرے برادر وطن کے خیالات کا پورا احساس ہے جیسا کہ کہا گیا ہے :

خیال خاطر احباب چاہئیے ہر دم -
انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو -

ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم احترام کرینگے - لیکن جبر نہ کیجئے - کمپیلشن نہ کیجئے - یہی ہمارا مطالبہ ہے -

اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کا مسئلہ ہے - واجپئی جی نے پوچھا کہ اقلیتی کردار کیا ہے - جب یہاں پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نیا بل پیش تھا - اور اس پر بحث ہوئی تھی تب میں نے تفصیل کے ساتھ بتلایا تھا - کہ اقلیتی کردار کیا ہے - کیسے علی گڑھ یونیورسٹی بنی - کس کس نے قربانیاں دیں - انڈاومینٹ قائم کئے ، عمارتیں بنائیں ، پیسہ دیا ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مسلمانوں نے مسلمانوں کے لئے قائم کیا - لیکن اوروں کے لئے دروازہ بند نہیں کیا اس یونیوورسٹی کے پہلے گریجویٹ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ تھے -

چند سال پہلے مسلم یونیورسٹی کے سلسلہ میں سفارشات کرنے چھتر جی کمیشن بٹھایا گیا - اس نے مسلم یونیورسٹی کے خاص کردار کو سکے رکھتے ہوئے سفارش کی تھی کہ وہاں پر ۳۵ فیصدی نان مسلم اور ۶۵ فیصدی مسلم طلبہ ہونے چاہئیں - انہوں نے یہ تناسب بتایا تھا - ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے قائم کیا تھا - اپنے خون جگر سے سینچا تھا ۱۰۰ سال تک پالا پوسا - اس پر ہمارا کنٹرول رہے - اور یونیورسٹی کے طلبہ کی تعداد میں اساتذہ کی تعداد میں مسلمانوں کی اکثریت رہے -

جہاں تک مسلمانوں کی اقتصادی حالت کا تعلق ہے متعلیمی دلعں کا تعلق ہے وہ آج بھی بہت پچھڑے ہوئے ہیں - واجپئی جی نے کہا کہ اقلیتیں کچھ بھی نہیں ہیں - یہ غلط ہے - اقلیتیں ہیں اس ملک کے سیکولر کریکٹر میں - ان کے لئے جگہ ہے فنڈامینٹل رائیٹس ہیں - سب کچھ ہے - اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا - اس دیش میں سیکولرزم ہے - اور اسی کی بنیاد پر ہم اس ملک میں اپنا حق چاہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں فنڈامینٹل رائیٹس دئے ہوئے ہیں امید ہے - واجپئی جی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرینگے - ورنہ میں کہوں گا :

اگر اب بھی نہ سمجھے -
تو پھر تم سے خدا سمجھے -

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT): Mr. Deputy Speaker, Sir, after listening to the hon. friend Shri Sait (I am rather surprised that he does not always speak in Urdu, I found that he was very very fluent in Urdu), who ended his speech on a very happy note by offering to have a dialogue with Shri Vajpayee, I hope that their dialogue does not result in excerbating communal situation because as Shri Vajpayee says there are two edges to one sword perhaps, two sides to each coin and that dialogue. I hope it will result in a kind of philosophy which will lead to the lessening of the political power of both.

15.40 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

Sir, many points were touched in the debate as is always the case in Home Ministry's debate and as the Home Minister is going to reply to the debate, I shall confine myself to a few specific points.

The first of these is with regard to the freedom fighters. Several hon. friends have raised it and many others who have not got the chance would have raised it if they had got the chance like my friend opposite. This is a subject on which there can be two opinions. The need of a large number of freedom fighters is acute and there has been some delay and because of that many people, many freedom fighters in all parts of the country are rather worried. But I would to assure the House that we are speeding up the whole process of the disposal of the applications which we have received. Shri D. N. Tewari mentioned the figure of 6,000 applications which had been approved. This figure related to 21st December, 1972. Thereafter we increased the tempo of work. More persons were recruited. Actually the staff was increased four fold and by the 15th of February, the total number of applications received was 1,19,583. Out of these 10,161 cases had been approved for pension and one thousand and odd cases had been rejected. Further steps were taken to expedite the disposal and I have individually talked to many hon. friends in regard to what steps we have taken. On the 15th March, 1973 the number of applications received was 1,24,184 and 20,920 had been sanctioned.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: Please give Statewise figures.

SHRI K. C. PANT: I can collect Statewise figures, if you want. About 3,315 cases have been rejected as not being eligible and in 16,803 cases clarifications have been asked for from the applicants or various authorities. The total number of applications scrutinised till 15th March, 1973 is 41,069.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Is scrutiny done? Is priority given according to the receipt of the applications? How is the process being done?

SHRI K. C. PANT: Till 15th March, 17,000 applications have been scrutinised and pension was sanctioned in 10,000 cases.. Now I shall give you the figures at a still later date, 27th March, 1973. The total number of applications received was 1,25,974; the number of applications processed—41,618; number of applications disposed of 27,161; number of cases provisionally sanctioned—23,178; number of cases rejected—3,983; number of applications where we are awaiting reports on clarifications asked for by us—14,457.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj): What are the clarifications?

SHRI K. C. PANT: What happens is this. When a freedom fighter applies, he does so in duplicate; one copy is sent to the State Government and the other, to the Central Government.

[Shri K. C. Pant]

Where all the papers are complete, we sanction the pension straightaway, provisionally. There is no diarchy as Tiwaryji thought, in the sense we do not wait for further clarifications from the State. In cases where the information we have received is in order, we sanction it provisionally; thereafter verification comes in due course. But sometimes papers are not complete; for instance, sometimes the M.P., the M.L.A. or the ex-M.P. says in the certificate: Mr. X has been in jail with me; they do not say he had been in jail for six months. Since it is one of the conditions to be fulfilled, we have to refer it back.

SHRI D. N. TIWARY: There is record for the period he was sentenced. He enters one jail and is transferred to another jail. He is required to submit a certificate from that jail which is not available.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बहुत से एम पीज ने लिखा है कि यह 6 महिने मेरे साथ जेल में थे लेकिन उसके बावजूद अभी तक दरख्वास्त पेंडिंग है ।

श्री के० सी० पंत : यह सम्भव है लेकिन वह रेजेक्ट नहीं होगी । इस बिना पर वह रेजेक्ट नहीं होगी. यह मैं आपको विश्वास दिलाता हुं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो पूछा है उसका जवाब मैं दूंगा कि किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं ।

We reviewed the position again and the State Governments have been asked to send us verified lists. Mishraji suggested that the State Governments should set up district-wise all-party committees. In Bihar they have set up such a committee at the State level, in which I think probably the representatives of most of the parties opposite are sitting.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: They are not functioning in that way; they should go to every district and within two or three days finalise all these applications.

SHRI K. C. PANT: We have suggested it to the State Governments and we have left to the State Governments to do so; we have asked them to send us verified lists conforming to our scheme and if they send such a list, we shall accept that list without going any further into it.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: Is there difficulty on your part to make the suggestion that an all party committee should visit every district and finalise these applications? They are put to so much inconvenience and trouble.

SHRI K. C. PANT: I think they would also require some records.... (*Interruptions*) I shall come to the record part also. Committees have been set up by some States and we have told them that we shall accept their lists provided they correspond to our scheme. Otherwise we have to check independently. No State has actually sent us such a list. We have written to the States to write to the District Magistrates to help freedom fighters in procuring jail certificates.

But, still, there are difficulties. Now, some States have sent us some lists—verified lists—of applicants. But we find that they were not verified fully in accordance with our scheme. We are trying to get the new lists from the States according to our Scheme. Some States have got their own schemes which do not correspond with those of ours. For instance, U.P. have given some applications which do not correspond to our scheme. They correspond to their own schemes. These are some difficulties. It is our intention to scrutinise about 16,000 applications per month. Our intention is that by 15th August, 1973 all applications would be scrutinised which have been received

by the Centre. We would see that pension is sanctioned to as many people as possible.

Sir, a point was made about the jail certificates. The problem here is that in some places, the people cannot find the jail certificates. They say that they are destroyed. Our problem is that in the case of one State, when we published a list of freedom-fighters in the beginning, on scrutiny we found there were difficulties. These are the cases of some freedom fighters. We should not be strict and that let us give them pension. We published the lists. Regarding some freedom fighters the Government objected to certain names. We said that these must be scrutinised more fully. It is not proper to sanction pension. These have created immediate difficulties. In complaints of this kind we have to be more careful in scrutinising them. One suggestion which Shri D. N. Tiwary made was this that the certified copies of the judgments should be accepted in lieu of jail certificates. Here the difficulty of course is quite obvious. Suppose one undergoes the sentence of imprisonment. How long could he stay in a jail? He might have got out of the jail. But, I am prepared to consider this. I am prepared to consider whether we can give provisional pension on the basis of certified copies of the judgment. But, of course, we have to check them up further. Subject to this, I think that this will resolve one of the difficulties. I am prepared to accept this suggestion.

SHRI D. N. TIWARY: There is a record from the jail that this man was sentenced for nearly six months or one year. And he lived in the jail for one month and thereafter he was transferred to some other jail. But, that jail authority has not given the certificate since they do not have the records.

SHRI K. C. PANT: Our difficulty is that there are complaints from persons about pension. Sometimes there are complaints that they stayed in the jail for some time and they came out of it. These are the things that we have to keep in mind. We have to be very careful. I hope that the hon. Members will feel satisfied with the difficulty in the matter of acceleration of the pace of disposal of applications which I place before the House. You know we have asked the MPs, M.L.As, Ex. M.Ps. and Ex. M.L.As., District Magistrates and State Governments to certify. In future we will accept such certificates. But, I do know whether we can go beyond that. Shri Tiwary had made his suggestion. If there are any other suggestions, we shall welcome them also. I may assure you that we shall take a most sympathetic view of the things as much as possible.

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछलीशहर) : बहुत से आदमीयों पर केस चला, साल-साल भर जेल में बन्द रहे और बाद में मुकदमे में छुट गये । उनके बारे में क्या होगा ?

SHRI K. C. PANT: Many people have been detained in jails for more than six months and they have been convicted. There we accept it. We can accept the period of undertrials also. Where they have been released, in an ordinary case also, you will have to give us some proof. Apart from merely being an undertrail, it has got to be related to the freedom struggle.

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI (Their-Garhwal): What procedure have you evolved about freedom fighters in NWFP and other areas which are now part of Pakistan?

SHRI K. C. PANT: Wherever possible, we have set up small groups of persons or even single persons in some cases who have personal knowledge and are familiar with the freedom fighters of those areas and we accept their certificates.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: What about revolutionaries? They come under a different section.

SHRI K. C. PANT We realise that sometimes sections of the IPC are used which are not unrelatable to the freedom struggle but the history of the person can very often give us the clue as to what the real intention of the Government was. We do take that into account.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: Will you see that their cases do not suffer?

SHRI K. C. PANT: We will certainly try to see that their cases do not suffer.

In all cases where the applications are received till 31st March, 1973, whenever they are sanctioned later in the year and in cases which have already been sanctioned, pension will be given retrospectively with effect from 15th August, 1972. In the case of applications received after 31st March 1973, they will be given from the date of receipt of the applications and not retrospectively. This I want to make clear so that there is no confusion.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: This is a very serious matter. The Minister must give sympathetic consideration to it. If the person concerned is not able to collect all the documentary evidence not because of his fault but because the evidence is lacking in the offices concerned. If he is able to collect all those papers after 31st March 1973, why should he be put to any kind of inconvenience or difficulty?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT): He can write to us within this time that he has suffered, that he comes within the defined category but he has not yet got the necessary evidence and he is collecting the evidence. Such cases can be considered. But if a person himself does not know, how can it be done?

SHRI INDRAJIT GUPTA: Even for that if they after tomorrow is the dead line, it will be very difficult.

SHRI K. C. PANT: Previously the date fixed was 31st December. Then we liberalised it and extended the date upto 31st March. But I am not prepared to take a hard and fast attitude towards this question. If the House thinks that some extension is desirable, we will extend it.

The hon. Member asked about the procedure for dealing with the applications. They are dealt with on a chronological basis, first received first served. The only exceptions are about people who are very old and very ill. We have two categories—over 70 years and over 80 years.

AN HON. MEMBER: Many people will die by that time.

SHRI K. C. PANT: Many people have died in the last 25 years, about which we could not do anything. With all the sympathy in the world, there has to be a certain method and procedure for dealing with these applications. I can think of no better one. Those who are very old, or ailing, or in dire need of financial assistance are given preference among thousands of applicants. Only these applications are taken out of turn, and I hope my hon. friends will be satisfied with this procedure.

16 hrs.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: Why not have an advisory committee at the Central level with which all political parties are associated?

SHRI K. C. PANT: Then, a lot of criticism was made about the police and mention was made of individual incidents. Shri Mishra referred to the Miranda House incident, in spite of the long debate here. There was general criticism. I do not want to deal with the Delhi Police first. I will deal with it later because Delhi is our direct responsibility.

So far as the whole country is concerned, whether it is the police, or public order, or administration of Jus-

tice, these are subjects which are within the State sphere; they are not within the Central sphere. Our role in this matter is only to assist the States in the discharge of their duties in a more satisfactory and efficient manner. Whenever the States ask for our armed forces, we supply them. That is why we have strengthened the CRP.

We have gone into the matter of the efficiency of the police force. While I cannot answer for the police force of the State, so far as CRP is concerned, we have gone into the question of its efficiency, its mobility, its discipline, what we can do to equip it for maximum efficiency etc. These are all points which we have considered.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: How many battalions of CRP have you got?

SHRI K. C. PANT: I do not have the figures with me here. He can ask a question.

So far as CRP is concerned, the demand from the States is so much that we have not been able to give the CRP men and officers the rest they deserve and then rotate them. We want to send them to a State, bring them back and then send them to another State and have a cycle like that. We are not able to bring them back as fast as we would like. In fact, some of the battalions have been on the field, non-stop for months together. The reason is that there are problems which the States put before us to which we cannot say "no". Therefore, the CRP has been used.. ..(*Interruptions*) I do not know whether it helps anybody to have these running commentaries.

So far as the general question of police in the States is concerned, I would like to refer to some specific measures designed to help the States with their police force. Firstly, we have taken the initiative in constituting a broad-based committee consisting of experts to go into the question of the training given to police. Reference was made to this committee in the House. This Committee has recently given its report. We are going in to the report. We want to implement it as expeditiously as possible. This is one important step that we have taken. Then, several central institutions have been set up to go into more specific aspects of police functioning.

Here, without going into further details, I will just refer a few. The Central Bureau of Public Administration, which is primarily designed to undertake studies in depth of specific problems faced by the Police in day-to-day matters. Such studies in depth range from a systematic appraisal of police organisations in general in communally sensitive districts. This is a matter about which we have been concerned and therefore, we are devoting special attention to this matter. Secondly, there are questions like the operational efficiency of different sysems of the police forces. Then, we have the Central Police Academy, the Forensic Institute and Finger-print Bureaus etc. All these are designed to help the Central police forces as well as the State police forces.

Then, Sir, Centre is giving financial assistance to improve the mobility of the State police forces, their equipment, investigation etc. and since 1969-70, Rs. 15.5 crores have been made available to the States for such schemes. A provision of Rs. 8 crores has been made in the Budget for the next year. Here, without going into further details I would.....

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: What about assessment of the performance of CBI, as to whether it functions impartially and objectively or not?

SHRI K. C. PANT: My problem is that the CBI is not under the Home Ministry.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: We really do not know. In regard to allocation of business, which has been made according to the latest

[Shri Shyamanandan Mishra]

circular, only the subjects like the scheduled castes and the scheduled tribes seem to belong to the Home Ministry.

SHRI K. C. PANT: We are rather proud that the subject of scheduled castes and scheduled tribes belong to the Home Ministry.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order. If we want to discuss subjects which involve the Prime Minister, like the Cabinet Secretariat, CBI and Research and Analysis Wing etc. for which we pay every year, what is the forum?

सभापति महोदय : होम मिनिस्ट्री से सम्बन्धित जितनी भी बातें हैं उन्हें वह कहिये

SHRI G. VISWANATHAN: Under this, we can discuss CBI.

MR. CHAIRMAN: He says that CBI is not under the Home Ministry. So, he is not touching that point. (*Interruptions*)

SHRI K. C. PANT: On a point of order. We are in the midst of a debate. I am trying to reply to some of the points raised. Can this debate be interrupted just now to find out the allocation of certain other items? I am only concerned with the Home Ministry. If this debate is diverted to other channels, we lose time for the Home Ministry debate. This is the Budget Session. Let us finish with the Home Ministry debate, and thereafter, any hon. Member can raise any point. But, this should not be at the cost of the time allotted for the Home Ministry.

MR. CHAIRMAN: If that subject is not under the Home Ministry, he is not bound. Hon. Members are so ignorant that they do not know as to what subject comes under what Ministry.

SHRI G. VISWANATHAN: We want the Chair to throw some light on it.

MR. CHAIRMAN: It is not the business of the Chair to enlighten the Members which subject is under what Ministry. It is the business of the Members to acquaint themselves. (*Interruptions*)

SHRI K. C. PANT: I would like to tell my hon. friends that they can discuss this matter under the head "Cabinet Secretariat".

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: I have the Report of the Home Ministry here, On p. 9, it mentions, "Central Bureau of Investigation (Coordination Division)". It is with the Ministry of Home Affairs. The Minister is misleading the House. Why does he not state the truth?

SHRI K. C. PANT: I am stating the truth....

MR. CHAIRMAN: He is denying it....

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: I have got the Home Ministry's Report here. I am quoting from that. You are pleased to call the Members ignorant. I say, the Minister is ignorant. He does not say that it has been disbanded. In order to escape the criticism about the functioning of the C.B.I., the Minister cannot take that stand.

SHRI K. C. PANT: A senior Member like him speaks in this manner. After all, this is not a secret thing. This is something which could be easily found out. (*Interruptions*) what is the use of interrupting me again and again? Why don't you have patience to listen to me?

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: I am addressing my remarks to the Chair.

MR. CHAIRMAN: He says, this allocation is an old allocation. You may find out the new allocation.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: It is nowhere mentioned in the Report that this Division has been disbanded in the Home Ministry. You are not supplying us the proper material; the Parliament Secretariat is not supplying the proper material.

MR. CHAIRMAN: They must have issued some literature in which new allocations must have been given. You may please consult that literature.

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka): What is under discussion today is the Home Ministry's Report, not the allocation of work. This is the Report which has been supplied to us.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: To put the records straight, I may say that we have directed our criticisms against the functioning of the Central Bureau of Investigation during 1972-73. We are not directing our criticisms about the future functioning of that organisation. I am perfectly in order when I say that the Home Ministry has to bear the burnt of criticism for 1972-73 even if the Minister is taken to be right in that it has been disbanded so far as his Ministry is concerned.

PROF. MADHU DANDAVATE: What is wrong in discussing the C.B.I.?

SHRI K. C. PANT: There is nothing wrong in discussing anything. What I mentioned was that if you want to deal with matters concerned with the C.B.I., I will not be able to answer. (*Interruptions*) Why don't you listen to me?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वह सी०बी०आई० के बारे में जवाब नहीं देंगे । मैं आपका मार्ग-दर्शन चाहता हूं कि सी०बी० आई० के बारे में कौन जवाब देगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : 1972-73 के बारे में कौन जवाब देगा ?

SHRI K. C. PANT: If they are interested seriously in knowing, I am here to say whatever I know; if I am wrong and I am corrected, I am prepared to accept the correction. If I mislead the House and if they say that I misled and then I find that it was incorrect, I will come to the House. But they should have the patience to listen to me. The simple position is that my hon. colleague, Shri Ram Niwas Mirdha, and the Prime Minister look after CBI. We do not look after CBI in the Home Ministry. That is in the Cabinet Secretariat. (*Interruptions*) I am nobody to shut out discussion of those points, it does not lie within my power; but I am entitled to say that something of which I am not aware, I cannot give an answer to.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी श्री पन्त ने कहा है कि उनके सहयोगी, श्री मिर्धा, सी०बी० आई० की देख-भाल करते हैं । श्री मिर्धा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं । गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री, जो सी०बी०आई० की देख-भाल करते है, जब सदन में है, तो क्या वह गृह मंत्रालय की तरफ़ से उत्तर नहीं दे सकते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं तो नहीं दे सकता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह होम मिनिस्ट्री में नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह होम मिनिस्ट्री में नहीं है ।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) सभापति महोदय, सी०बी०आई० कैबिनेट सैक्रेटेरियट के दायरे में आता है और कैबिनेट सैक्रेटेरियट गृह मंत्रालय से जुदा है । मैं गृह

[श्री राम निवास मिर्धा]

मंत्रालय में कुछ काम देखता हूं और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हूं। उसी तरह से मैं कैबिनेट सैक्रेटेरियट में भी राज्य मंत्री हूं। उस नाते मैं सी.बी.आई. के काम को देखता हूं।

SHRI K. C. PANT: I hope, the position is now clear.

There was some discussion about Delhi Police and there was severe criticism of this Police. I do not want to go into the details of this. Ten minutes have already been taken up in the other discussion and, therefore, I cannot deal with this matter in the detail in which I would like to deal with it. But, Sir, I would refer, very briefly, to the fact that we have been taking some measures in answer to the debates in the House, in answer to the facts and the ground; we realise that special attention has to be paid to the crime situation in Delhi. At the same time, while there are a few instances and those instances naturally come up for discussion in the House and a certain picture is painted—I would like to assure the House that there are a very large number of policemen who are doing their duties as well as they can, and a word of appreciation about this section of the police force would go to encourage their morale also. It is true that we have, ultimately, to control this situation. At the same time, if we find that anybody is at fault, we can assure the House that we shall be very very strict with them.

There was some reference to the fact that criminal cases are not registered in many Police stations. It used to be a complaint which is heard much less now and if my hon. friends look at the figures of crime—I have given the figures in this House—you will find that from 1970 onwards there was been a sudden leap in the crime figures which is at least partly due to the fact that we have been insisting on proper registration of the crime figures and this is partly reflected in the increased crime figures. Since 1970 you will find a jump.

We have a twelve-point programme which has been set in operation to control the crimes. Preventive patrolling, more intensive vigilance, activising the Missing Persons Squad, deployment of plain-clothed Policemen, organization of selective raids and improvement of control room techniques are some of the salient features of the twelve-point programme.

With regard to women, certain remarks were made and I can assure the House that greater vigilance is being shown in respect of crimes affecting the dignity of Indian women and there, we have told all levels of the Police officers, supervisory and otherwise, to pay special attention to this.

I think, Shri Virbhadra Singh referred to some measures which should be taken to improve the functioning of the Police. He is not here, but I can assure him that all those aspects which he mentioned—modernisation of the police.... (*Interruptions*) I am not yielding. There is very little time now.

Shri Virbhadra Singh has referred to some aspects. We have accepted his advice and we have already been acting on it—modernisation of the Delhi Police force and so on and the triennial review is going on with regard to the strength of the forces. We are looking into the question of larger deployment of women police also. This is in regard to the Delhi Police.

I would like to refer very briefly to this rather extra-ordinary incident of the surrender of 459 dacoits in the Chambal area last year.... (*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE: Serious allegations were made to the type of campaign that Shankaracharyaji of Puri has been carrying on in Maharashtra and as a result of that there are demonstrations at very

meeting of Shankaracharya and there is a threat to peace....

SHRI S. A. SHAMIM: Unless he surrenders, what is the use of the dacoits' surrendering?

SHRI K. C. PANT: I am not dealing with all the points. As I said in the beginning I shall deal some specific points. That is why I seek the indulgence of the House that if I do not reply to each and every point raised in the debate....

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTAHAMMA: An hon. Member referred to the vicious propaganda Shankaracharya is spreading, campaigning for untouchability and insulting women and the status of women, comparing them to cats and dogs. Has this House no right to get a reply from the Minister to that?

SHRI K. C. PANT: We shall examine the speeches made. I can assure the hon. Member, but I can only speak about it if have gone into the matter. Before coming to the House I have chosen certain subjects on which I will speak but you must appreciate that I am very responsible for what I say in the House....

श्री शम्भूनाथ (सैदपुर) : प्वाइंट ग्राफ ग्राडंर । पंतजी शेड्यूड कास्ट ग्रौर शेड्यल्ड ट्राइब्स के मामले के डायरेक्टली इंचार्ज हैं ग्रौर शंकराचार्य ने कहा है कि सोशल इनईक्वलिटी जो समाज में है वह जस्टिफाइड है जिसका मतलब यह भी निकलता है कि ग्रनटचेबिलिटी जस्टिफाइड है . . . .

सभापति महोदय : प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर क्या है ?

श्री शम्भूनाथ : जरा सुन लीजिए । चूं कि होम मिनिस्ट्री में शेड्यल्ड कास्ट ग्रौर शेड्यल्ड ट्राइब्स का मामला ग्राता है ग्रौर ये डायरेक्टली उसके इंचार्ज हैं ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी यह है ग्रौर इस पर वह जवाब दें ।

PROF. MADHU DANDAVATE: I want to bring to your notice that this matter was brought to the notice of the Speaker. A call attention was given and a short notice question was also given. Mr. Speaker also said: Your indignation is quite genuine but due notice will be taken by the Home Minister when the debate takes place. That is why I appeal that this matter should be taken up in all seriousness. Please don't take it in a casual way..

SHRI K. C. PANT: There is no question of taking it in a casual way.

MR. CHAIRMAN: Without hearing his reply, how can you say that? There is no point of order in what the other hon Member said.

SHRI K. C. PANT: I may say that I am not directly in charge of this question. But, that makes no difference at all. I am equally anxious in seeking that justice is done. I said already that we will look into the statements.

I was mentioning about the surrender of 459 decoits. There is no major decoit gang now in that area. This is to be viewed against the background that for centuries the decoit menace had infested that area and successive Governments were not able to solve this problem. Since April 1972 last year series of surrenders have taken place. Sarvodaya workers have helped. The Government of Madhya Pradesh, Rajasthan and U.P. have cooperated and the Central Government has cooperated. Mr. Jayaprakash Narain played a very big part in this. Now the effort is being made to bring about a permanent change in that area. Their socio-economic problems are being tackled. There are four sub-groups which have been set up by the Committee of Joint Secretaries. They have got to

[Shri K. C. Pant]

work out plans for reclamation, irrigation and cultivation; secondly, roads and thirdly, communications, and fourthly, social, economic and industrial development. I would like to say that a scheme costing about Rs. 250 to Rs. 350 crores over a five-year to seven year period is prepared. Rs. 1 core has already been provided for the development of Chambal vally area during 1973-74.

Mrs. Chanda and Mr. Basumatari referred to the Assam-Cachar situation. Mr. Mishraji also said that Central Government has not taken action in the matter. Without going into the details I would like to assure the House that the Central Government is always in continuous touch with the situation in Assam and Cachar.

सभापति महोदय : साढ़े चार बजे श्री गणेश मणिपुर का बजट पेश करने वाले हैं। तो उसके बाद क्या आप बोलेंगे ?

श्री के० सी० पन्त : मैं पांच मिनट में खत्म कर दूंगा।

The situation in Assam is now far more reassuring than it has been for a long time past. We don't have any rigid stand in the matter. It is for State leaders, leaders of public opinion in the States to come up with the right solution and discuss amongst themselves. We in the Central Government are always ready to offer our good services. There was once a discussion at Delhi between leaders of Cachar and Assam and Assam and ourselves and some progress was made; later on they are meeting amongst themselves and they are going to meet again. So, this is going on, and I do not want to touch on the basic problem of language in Cachar for fear of raising emotions. So I am leaving this out but I may say that the process of finding out a solution is already going on.

The question of students is there. Some students returned from Tripura to Dibrugarh. There were certain incidents which caused students from Tripura to go back to Tripura. I am glad to inform the House that the Assam Government took prompt steps and sent some of their Ministers and some leaders there. Most of the boys have come back to Dibrugarh. Still there are some boys in Calcutta. Assam Government has sent one of their Ministers there. Shri D. K. Borooah has also gone to Calcutta and they are trying to persuade the boys from Assam in Calcutta to go back to the universities in Assam.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: What Mr. Bhagat's mission has done?

SHRI K. C. PANT: It has helped in lubricating the whole process. The efforts are continuing and I hope the students will go back soon.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: What about the Central responsibility for the linguistic problem?

SHRI K. C. PANT: I want to make it clear that so far as the Centre's responsibility is concerned I can easily put before you the result of the Chief Ministers considering this matter in 1961 and said this is the formula and that is the formula. But that hardly helps.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: At the moment how are you thinking of solving this problem?

SHRI K. C. PANT: We would rather leave it to the leaders of Assam and Cachar to arrive at a solution. Our good offices are there. We would not like to thrust a solution on them. We will see to it that a solution is brought about but the initiative has to come primarily from them. I do not want to go into other aspects of this matter at this stage. My only hope is that the discussion which are going to continue next month will be successful.

A word about the North-East Council which has begun functioning and which the Prime Minister inaugurated on the 7th November, 1972. This is a step in the direction of the regional development of the whole north-east area. My friend, Shri Virbhadra Singh, wanted a similar council for the north-western region. The zonal council is there for the north-west area. In the North-East alone because of geographical situation this kind of Council has been thought to be the best method of development. I will only say that Rs. 50 cores have been set apart for the integrated development of the region apart from the plans and the Centre will finance the schemes for integrated development. We attach a lot of importance to the development of North-eastern region. We hope Nagaland which has not joined this Council will see the advantages accuring from this Council and will join soon.

Regarding Andhra, while the House is aware of all the aspects of this question. The present situation is that the talks are still continuing. All I would like to say on this occasion is that I would like to congratulate the NGOs for returning to work. That will certainly help in normalisation of the situation in Andhra Pradesh. I would also like to take this opportunity to appeal to the students to return their studies and not to allow another year to be wasted.

16.36 hrs.

MANIPUR BUDGET, 1973-74

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up Manipur budget.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): Sir, I present a statement of the estimated receipts and expenditure of the State of Manipur for the year 1973-74.

The House is aware that by a Proclamation of the 28th March, 1973, under Article 356 of the Constitution of India, the President assumed to himself all the functions of the Government of the State of Manipur and all powers vested in or exercisable by the Governor of the State. Under the Proclamation, the Legislative Assembly of the State stands dissolved and the powers of the Assembly are to be exercised by or under the authority of Parliament. Accordingly, I lay before the House the Annual Financial Statement of the State of Manipur for the financial year commencing on the 1st April, 1973. The House will be moved to make supplies needed for the first four months of 1973-74.

With your permission, Sir, I wish to make a brief mention of the broad features of the estimates.

Revised Estimates, 1972-73

The revenue receipts for the year shortly coming to a close are now estimated at Rs. 18.93 crores, marginally lower than the original estimate of Rs. 18.99 crores. The expenditure met from revenue, estimated at Rs. 19.45 crores, however, exceeds the original estimate by Rs. 46 lakhs due mainly to higher expenditure on Agriculture, Education and Test Relief Works. As a result, there will be a deficit on revenue account of the order of Rs. 52 lakhs. On the capital side, the deficit will be of the order of Rs. 2.26 crores, against the original expectation of a balanced budget, resulting in an overall deficit of Rs. 2.78 crores.

Budget Estimates, 1973-74

For 1973-74 the estimates of revenue receipts are placed at Rs. 21.57 crores, reflecting an increase of Rs. 2.64 crores over the revised estimates for the current year. Expenditure on revenue account will be Rs. 22 31 crores, resulting in an estimated deficit of Rs. 74 lakhs on re-